सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 39 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 22 नवंबर 2025 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

छत्तीसगढ़ भविष्य के लिए तैयार टेक्नोलॉजी वाला राज्य बना, AEIM को 11 एकड़ जमीन अलॉट

- कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन 2026 में शुरू होने की उम्मीद

श्रीकंचनपथ न्यूज

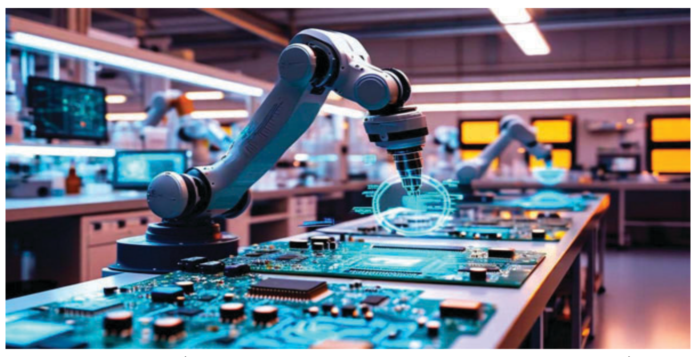

रायपुर। भारत के हाई-टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़ने के संकेत देते हुए, पॉलीमेटेक ग्रुप की कंपनी, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंट मटेरियल्स लिमिटेड (AEIM) को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने मशहूर पॉलीमेटेक इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर 11.28 एकड़ प्राइम इंडस्ट्रियल ज़मीन अलॉट की है। यह स्ट्रेटेजिक अलॉटमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के नेक्स्ट-जेनरेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की ओर मज़बूत कदम बढ़ाने के बाद आया है, जिसे 40 फीसदी तक की कैपिटल सब्सिडी से और मज़बूती मिली है, जिसे इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव में से एक माना जाता है।

इनोवेटिव पोस्ट-टेंशन्ड स्लैब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

AEIM की स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सेमीकंडक्टर मटीरियल फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन नवंबर 2025 में तुरंत शुरू होने वाला है। कंपनी की आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग टीमें इनोवेटिव पोस्ट-टेंशन्ड स्लैब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी, जिससे बड़े स्ट्रक्चरल स्पैन और कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में काफ़ी कमी आएगी। हर फ्लोर पर सिर्फ़ 10 दिनों में डी-शटरिंग हो सकती है, इसलिए AEIM का टारगेट मई 2026 तक अपने मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पहला फेज पूरा करना है।

रायपुर को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जगह देगी

इस माइलस्टोन पर कमेंट करते हुए AEIM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, विशाल नंदम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से मिला सपोर्ट इंडस्ट्री कोलेबोरेशन के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है। यह वर्ल्ड-क्लास फैसिलिटी रायपुर को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जगह देगी। हम 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा कर रहे हैं और युवा इंजीनियरों के लिए 4,000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स पैदा करेंगे, जिससे इस इलाके में स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वाइटैलिटी को बढ़ावा मिलेगा।

“ छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट विज़न पर काम कर रही सरकार : सीएम साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार का डेवलपमेंट विज़न छत्तीसगढ़ को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर-रेडी इंडस्ट्रीज़ का एक लीडिंग हब बनाना है। नवा रायपुर में AEIM की सेमीकंडक्टर मटीरियल फैसिलिटी का बनना इस विज़न की बढ़ती रफ़्तार को दिखाता है। वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोएक्टिव पॉलिसी और भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव स्ट्रक्चर में से एक वाला एक अच्छा इकोसिस्टम बनाकर, हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के अगले 25 सालों की ग्रोथ को शेप देंगे।

खास-खबर

तेज रफ्तार बुलेट अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, चालक की हुई मौत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ग्रामीण की तेज रफ्तार बुलेट गड्ढे में गिर जाने की घटना में चालक की मौत हो गई। भतीजे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है, मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, राम लकड़ा ने लैलूंगा थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि वह बिछीनारा का रहने वाला है। राम ने बताया कि कल उसका चाचा जोहन लकडा बुलेट से अपनी दादी शाषिता तिग्गा के घर ग्राम पिपराही आया हुआ था। जहां से शाम करीब 5:30 बजे के आसपास वह अपने गांव बिछीनारा लौट रहा था। बाइक सवार जोहान लकड़ा जब ग्राम सुबरा कटंगपारा के पास पहुंचा ही था कि मोड़ आने से वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बाइक गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में जोहन तिग्गा के सिर, नाक और मुंह में गंभीर चोट आने पर उसे लैलूंगा अस्पताल ले जाया गया, जहां मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एनआईटी चौपाटी पर कार्रवाई: जेसीबी पहुंचते ही हंगामा, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी

- एनआईटी रायपुर के पास लगी चौपाटी को आमानाका शिफ्ट कर रही निगम
- कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के व्यापारी बैठे धरने पर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के एनआईटी चौपाटी को आज आमानाका शिफ्ट किया जाना है, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही विवाद बढ़ गया है। इसके विरोध में कल रात 11 बजे से व्यापारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत अन्य नेता धरने पर बैठे हैं। 22 नवंबर की सुबह निगम की टीम चौपाटी हटाने पहुंची। जहां प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता जेसीबी के सामने लेट गए और जेसीबी पर चढ़कर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और नेताओं के बीच झूमा-झटकी भी हुई। विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं और व्यापारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया और पूर्व विधायक को पुलिस उठाकर ले गई। फिलहाल सभी को सेंट्रल जेल ले जाया गया है।

शनिवार को जैसे ही निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, व्यवसायियों और कांग्रेस नेताओं ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध उस समय तेज हो गया, जब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष (निगम) आकाश तिवारी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता जेसीबी के सामने लेट गए। पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब वे हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

निगम ने दिया था शुक्रवार देर रात तक का समय

नगर निगम ने चौपाटी संचालकों को शुक्रवार देर रात तक (सुबह 5 बजे तक) जगह खाली करने की आखिरी मोहलत दी थी। अल्टीमेटम के बाद से ही तनाव बढ़ गया था। देर रात पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, आकाश तिवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यवसायियों के साथ वहीं धरना शुरू कर दिया था। सुबह जैसे ही मशीनें चौपाटी हटाने लगीं, दोनों पक्षों के बीच झूमाझटकी और नारेबाजी देखी गई। मौके पर सभी जोन के अधिकारी मौजूद रहे और चौपाटी हटाने का काम जारी है। निगम की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और जेसीबी लगातार तैनात हैं।

जिस स्थान का चयन वह निकली रेलवे की

चौपाटी को शिफ्ट करने के लिए निगम ने पहले जिस स्थान का चयन किया था, वह रेलवे की जमीन निकली। रेलवे उस स्थान पर ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसी वजह से रेलवे ने पहले से वहां काम कर रहे मैकेनिकों और अन्य व्यवसायियों को भी जगह खाली करने का नोटिस जारी किया है। रेलवे द्वारा भूमि पर अधिकार जताए जाने के बाद नई जगह पर चौपाटी स्थानांतरित करने की योजना अटक गई।

कांग्रेस का दोहरा चरित्र : साव

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा लोकतंत्र में विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीति के बारे में विचार करें वो किस दिशा में जाना चाहते है। क्या सोचते हैं। सत्ता में रहते हैं तो अलग बात करते हैं विपक्ष में रहते हैं तो अलग, कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहता हैं।

सड़क हादसे में युवती की मौत

- पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी, अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर

भिलाई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय आईटीआई के पास शनिवार की सुबह दर्दनाक हादसे में 29 वर्षीय युवती की जान चली गई। युवती राजनांदगांव से ट्रेन पर सवार होकर भिलाई पावर हाउस में उतरी और अपने पिता के साथ भिलाई तीन पदुमनगर अपने घर जा रही थी। इस दौरान अज्ञात भारी वाहन ने ठोकर मार दी। युवती की मौके पर मौत हो गई और उसके पिता घायल हैं। घटना की सूचना के बाद खुर्सीपार पुलिस ने शव को सुपेला मरच्यूरी भेज दिया। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक की तलाश है।

मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान साक्षी द्विवेदी (29) है। इसी वर्ष फरवरी में साक्षी की शादी राजनांदगांव में हुई थी। वह एबिस कंपनी राजनांदगांव में जॉब करती थी। हर सप्ताह शनिवार को वह पदुम नगर में अपने माता पिता के घर पर आती थी। इस शनिवार को भी वह सुबह की ट्रेन से निकली और भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरी। उसे लेने उसके पिता स्कूटी से पहुंचे थे।

पुलिस के अनुसार पिता के साथ साक्षी स्कूटी पर निकली और आईटीआई के पास भारी वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में साक्षी द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लिया और सुपेला मरच्यूरी भेज दिया। वहीं घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवती हर सप्ताह भिलाई तीन के रेलवे स्टेशन में उतरती थी और वहां से अपने घर जाती थी। इस बार वह भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतरी और हादसे का शिकार हो गई। बहरहाल खुर्सीपार पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई है।

दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा : पांच लाख में खरीदी थी एके-47, डीप फ्रीजर में रखे थे विस्फोटक

नई दिल्ली ए.। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार ब्लास्ट की जांच में खुफिया एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी मॉड्यूल द्वारा पांच लाख रुपये से अधिक कीमत में एके-47 राइफल की खरीद और विस्फोटकों को रखने के लिए डीप फ्रीजर का इस्तेमाल किया था। सूत्रों ने समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुझम्मिल ने फरीदाबाद से पकड़े जाने से पहले 2,500 किलोग्राम से अधिक अमोनियम नाइट्रेट जुटाया था और इसके साथ ही पांच लाख से ज्यादा में एके-47 राइफल खरीदी थी। यह हथियार बाद में आरोपी अदील के लॉकर से बरामद किया गया। एक खुफिया अधिकारी के अनुसार, यह हथियार खरीद इस मॉड्यूल की तैयारी और फंडिंग के स्तर को दिखाती है।

खुफिया अधिकारियों ने बताया कि डॉ. उमर बम बनाने के वीडियो, मैनुअल और ओपन-सोर्स कंटेंट ऑनलाइन देख रहा था। उसने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन नूंह समेत कई जगहों से खरीदे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के एनआईटी मार्केट से जुटाए। जांच में यह भी सामने आया है कि उमर ने विस्फोटक मिश्रण को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था। एक अधिकारी ने बताया कि फ्रीजर का इस्तेमाल मिश्रण को स्थिर और प्रोसेस करने के लिए किया गया। जो यह दिखाता है कि तैयारी कितनी व्यवस्थित और तकनीकी थी।

खैरागढ़ महोत्सव : समापन समारोह में शामिल हुए राज्यपाल डेका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कला और संस्कृति की प्रतिष्ठित धरती खैरागढ़ शुक्रवार की रात को रंगरस संगीत की रंगीन छटा से निखर उठी। बहुप्रतीक्षित खैरागढ़ महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि खैरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहर न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान है, बल्कि यह भारत की विविध कला-पद्धतियों का जीवंत केंद्र भी है। उन्होंने बताया कि यहां की संस्कृति रामायण काल से भी प्राचीन है। उन्होंने कहा कि संस्कृति के संरक्षण में ग्रामीणों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में कला के प्रति प्रेम और संरक्षण की प्रेरणा जगाते हैं तथा कलाकारों को अपने हुनर के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं।

समारोह में विशिष्ट अतिथि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खैरागढ़ भारत की कला-राजधानी के रूप में उभर रहा है और यह महोत्सव आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त करेगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. लवली शर्मा ने कहा कि खैरागढ़ महोत्सव विद्यार्थियों की साधना, सृजनशीलता और कला-अनुसंधान का सशक्त मंच है तथा विश्वविद्यालय भविष्य में राष्ट्रीय कला केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

समारोह में नृत्य संकाय के विद्यार्थियों ने कथक, भरतनाट्यम व ओडिसी नृत्य की सधी हुई प्रस्तुतिया दी। कोलकाता से आए मशहूर सरोदवादक उस्ताद सिराज अली खान और लंदन के तबला वादक पंडित संजू सहाय की जुगलबंदी ने संगीतमय वातावरण रचा। पंडित संजू सहाय के द्वारा तबला वादन की प्रस्तुति दी गई। पुणे की प्रख्यात कथक नृत्यांगना विदुषी शमा भाटे एवं उनके समूह ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी । राजनांदगांव की लोकगायिकाकविता वासनिक एवं उनके दल ने लोकसंगीत अनुराग धारा की प्रस्तुति दी।

भ्रूण हत्या का महापाप

भ्रूण की हत्या करना महापाप है। कंस ने तो देवकी के छह पुत्रों की हत्या उनके जन्म के बाद की। पर कलियुगी कंस तो बच्चों को गर्भ में ही मार रहे हैं। जिस तरह से कंस का अंत हुआ, उसी तरह इन महापापियों का भी अंत होना निश्चित है। श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में यह चेतावनी संत निरंजन महाराज ने दी। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में फर्क करने की अपसंस्कृति इसकी जड़ है। लोगों को लगता है कि बेटा उनके कुल का नाम रौशन करेगा। वो ये भूल जाते हैं कि बेटी दो कुलों का यश बढ़ाती है। होते होंगे कुछ लोग जो गर्भ का लिंग निर्धारण करवाते होंगे और फिर बेटी को कोख में ही मारते होंगे पर गर्भपात की यह इकलौती वजह नहीं है। यह अवांछित गर्भ से मुक्ति पाने का तरीका भी है। बलात्कार से ठहरा गर्भ, गलती से बने संबंध से ठहरा भ्रूण भी गर्भपात का कारण हो सकते हैं। करियर को प्राथमिकता देने वाले दंपती आजकल बच्चों की भी प्लानिंग करते हैं। कभी-कभी इसमें भी चूक हो जाती है। तब भी वे डीएनसी जैसी प्रक्रिया से गुजरने को विवश होते हैं। कलियुग में लोगों को देवी देवताओं से पुत्र प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। इसलिए विवाह से बाहर उत्पन्न सभी बच्चे अवैध होते हैं। समाज में उन्हें न तो स्वीकार किया जाता है और न ही उन्हें सम्मान दिया जाता है। वैसे भी गर्भ में लड़का या लड़की का पता लगाना अवैध है। दोषी को तीन से पांच साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। महाराज ने एक बात और कही कि विजयादशमी पर रावण का पुतला जला देने मात्र से राम राज्य की कल्पना साकार नहीं हो सकती। इसके लिए अपने मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करने से ही सही अर्थ में विजयादशमी का पर्व सार्थक होगा। अच्छा है कि लोग प्रवचन पंडाल में सुनी गई बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अन्यथा अगर बड़ी संख्या में लोग मन को मारकर बैठ जाते तो अनर्थ हो जाता। फिर मन की बातों का क्या होता? दरअसल, दो युगों को मिलाने की यही कोशिश एक ऐसे छलावे की तरफले जाती है, जो आपको यथार्थ से काट देता है। यह कलियुग है और कलियुग ही रहेगा। न तो यह सतयुग हो पाएगा, न त्रेता और न ही द्वापर। प्रत्येक युग की अपनी-अपनी विशिष्टता और खामियां रही हैं। कंस अपने भांजों को क्यों मार रहा था? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि बहन देवकी का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भविष्य में झांकने की ये कोशिशें आज भी होती हैं। यह और बात है कि इन भविष्यवाणियों पर आधुनिक समाज ज्यादा ध्यान नहीं देता। शिशु बलि, नरबलि, मन्नतों की बलि, सति प्रथा को समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। इसलिए अवांछित, विकारग्रस्त या अवैध संतानों के जन्म को यदि रोका जा सकता है, तो इसमें भी बुराई नहीं ढूंढना चाहिए।

संपादकीय

त्रासदी की जवाबदेही

यह खबर विचलित करने वाली है कि दिल्ली में एक सोलह वर्षीय छात्र और जयपुर में एक नौ साल की छात्रा ने स्कूल की असहज स्थितियों के चलते आत्महत्या कर ली है। निस्संदेह, ये आत्महत्या की घटनाएं एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती हैं। भारत के स्कूल, जिनका उद्देश्य बच्चों का पालन-पोषण और सुरक्षा करना है, तेज़ी से ऐसे स्थानों में बदल रहे हैं जहां क्रूरता, उपेक्षा और अनियंत्रित अधिकार बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां कोई असामान्य बात नहीं हैं; ये एक असफल व्यवस्था के लक्षण हैं। तीसरी भयावह घटना महाराष्ट्र के वसई की है जहां एक तेरह साल की छात्रा को किसी कारणवश स्कूल देर से पहुंचने पर शिक्षक ने अमानवीय सजा दी। छात्रा को स्कूल बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगाने को बाध्य किया गया। यह तथ्य नजरअंदाज करते हुए कि वह एनीमिया से पीड़ित है। छात्रा कुछ देर के बाद बेहोश हो गई और कालांतर में उसकी मौत हो गई। निस्संदेह, एक छात्र व एक छात्रा की आत्महत्या और महाराष्ट्र के वसई में छात्रा की उठक-बैठक लगाने से हुई मौत एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती है। स्कूल जिनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पालन-पोषण और सुरक्षा करना था, वे बच्चों के जीवन पर संकट की वजह बन रहे हैं। वहां शिक्षकों की संवेदनहीनता, उपेक्षा और सख्त व्यवहार कई बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां असामान्य बात नहीं, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता की कहानी कहती है। दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले किशोर ने अपने शिक्षकों के हाथों अपमान का हृदय विदारक वर्णन करते हुए एक पत्र छोड़ा है। उसके माता-पिता ने छात्र के उत्पीड़न का आरोप शिक्षकों पर लगाया है। उनका आरोप है कि उसे छोटी-छोटी बात पर डांटा गया, निष्कासन की धमकी दी गई और सहपाठियों के सामने मजाक उड़ाया गया।

> “ तीसरी भयावह घटना महाराष्ट्र के वसई की है जहां एक तेरह साल की छात्रा को किसी कारणवश स्कूल देर से पहुंचने पर शिक्षक ने अमानवीय सजा दी। छात्रा को स्कूल बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगाने को बाध्य किया गया। यह तथ्य नजरअंदाज करते हुए कि वह एनीमिया से पीड़ित है। छात्रा कुछ देर के बाद बेहोश हो गई और कालांतर में उसकी मौत हो गई। निस्संदेह, एक छात्र व एक छात्रा की आत्महत्या और महाराष्ट्र के वसई में छात्रा की उठक-बैठक लगाने से हुई मौत एक परेशान करने वाली सच्चाई उजागर करती है।

आत्महत्या करने वाले छात्र के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी में बताया गया कि छात्र ने मन में आने वाले आत्महत्या के विचार से काउंसलर को अवगत कराया था। लेकिन शिक्षकों ने न तो माता-पिता को सूचित किया और न ही उसे इस दिशा में सोचने से रोकने के लिये कोई सलाह दी गई। निश्चित रूप से जब कोई छात्र अपनी किसी गंभीर समस्या का जिक्र करता है तो ऐसे में उदासीनता हिंसा का एक रूप ही कही जाएगी। वहीं दूसरी ओर जयपुर में नौ वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सीबीएसई की जांच में संस्थागत उदासीनता का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पिछले 18 महीने से छात्रा अन्य छात्राओं द्वारा परेशान की जा रही थी। जिस दिन छात्रा ने आत्महत्या की, उस दिन वह अपनी सहपाठियों द्वारा लिखी गई, अश्लील सामग्री से स्पष्ट रूप से व्यथित होकर 45 मिनट में पांच बार अपनी शिक्षिका के पास शिकायत लेकर गई थी। शिक्षिका ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और उलटा उसे ही डांटा। निश्चित रूप से शिक्षिका ने छात्रा की देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। कमोबेश वसई की घटना भी शिक्षक की घोर संवेदनहीनता को ही दर्शाती है, जिसने एनीमिया से पीड़ित छात्रा से बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगवाई। हालांकि, शिक्षक को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छात्रा का जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। निश्चित रूप से तीन राज्यों में तीन विद्यार्थियों की मौत हमारी संवेदनहीन व्यवस्था को ही दर्शाती है। दरअसल, आज स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिये कारगर कानून के अलावा भावनात्मक संकट की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने की जरूरत है। स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाता होने चाहिए। साथ ही किसी बच्चे के भावनात्मक व शारीरिक शोषण रोकने के लिये सख्त दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ताकि भविष्य में किसी संभावना का यूं दुखद अंत न हो। इक्कीसवीं सदी के बच्चे नये दौर में नये सपनों की उड़ान लिए हुए हैं, वे अपनी अस्मिता व सम्मान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। एकाकी परिवार में वे मां-बाप के लाड-प्यार से पलते हैं। जब भी उनके अहम को ठेस लगती है वे असहज हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों का सतर्क व संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए पहले इसी अदालत द्वारा निर्धारित अपनी ही समय-सीमा वापस ज़रूर ले ली, पर असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खुला रहने दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

तमिल राजनीति और केंद्र-राज्य टकराव

प्रमोद जोशी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 20 नवंबर को राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए पहले इसी अदालत द्वारा निर्धारित अपनी ही समय-सीमा वापस ज़रूर ले ली, पर असाधारण स्थितियों में राज्यों के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खुला रहने दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायालय कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा है जब कोई राज्यपाल कानून बनाने की प्रक्रिया में ‘लंबी, अस्पष्ट और अनिश्चित’ देरी का कारण बने, तब राज्य सरकार अदालत की शरण ले सकती है। इस तरह से अदालत ने केंद्र और राज्यों के बीच एक जटिल राजनीतिक मुद्दे में नाज़ुक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8 अप्रैल के फैसले के कारण तमिलनाडु के जिन 10 कानूनों पर राज्यपाल की स्वीकृति मान ली गई थी, उनकी स्थिति क्या होगी। कुछ संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि वे कानून बन चुके हैं और उनकी अधिसूचना गजट में भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें स्वीकृत मान लेना चाहिए।

दशकों से देश राज्यपालों की भूमिका को लेकर विमर्श कर रहा है, पर रास्ता अभी तक नहीं निकला है। हां, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई मामले में फैसले के बाद राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी का चलन खत्म हो गया और सरकारों के बनने-बिगड़ने का स्वीकृत सिद्धांत बन गया। अप्रैल में न्यायिक-हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ था, जब गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर था। खासतौर से तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके सरकार भाषा तथा मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ से छूट को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव की मुद्रा में थी। इस मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। गत 15 नवंबर को उन्होंने एक और याचिका दायर की है।

इन बातों को अगले छह महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव की पूर्व-पीठिका के रूप में भी देखना चाहिए। देश में शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। इसे लेकर कई तरह के टकराव हैं। पिछले कुछ समय से तमिलनाडु सरकार ने तीन भाषा सूत्र, चुनाव-क्षेत्र परिसीमन और ‘नीट’ जैसे मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन मामलों के कारण राजनीतिक-कोलाहल तो हुआ है, पर बुनियादी तौर पर कुछ हुआ नहीं है।

इस साल अप्रैल में, उच्चतम न्यायालय के दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्यपालों के लिए लंबित विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित की थी। अदालत ने पहली बार यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें। यह निर्णय इस बात की स्वीकृति थी कि, हाल के दिनों में, राजभवनों ने विपक्ष शासित राज्यों में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों में देरी करके एक अवरोधक भूमिका निभाई है।

चूंकि अदालत ने राष्ट्रपति को विलंब के परिणामों पर सख्त समय-सीमा का निर्देश दिया था, इसलिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा। मई में सर्वोच्च न्यायालय को भेजे एक संदर्भ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस फैसले पर 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के प्रयास में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अतिक्रमण किया है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अदालत ने अब संतुलित रुख अपनाते हुए अपनी सलाह में कहा है कि न्यायपालिका को ‘विधायी प्रक्रिया में दखलंदाज़ी’ की अनुमति देना ‘शक्तियों के पृथक्करण की दीवारों को तोड़ना’ होगा।’ साथ ही यह भी कहा, ‘इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक समीक्षा भी मूल ढांचे का एक हिस्सा है... हालांकि, यह न्यायिक समीक्षा कोई बेलगाम दायरा नहीं है जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को नकार या नष्ट कर सके।’

केंद्र सरकार ने भी अप्रैल के फैसले को लेकर टकराव पैदा करने के बजाय, न्यायालय से राय मांगकर अच्छा किया। वस्तुत: राज्यपाल को ‘रबर स्टैंप’ मानना भी अनुचित है। संविधान ने राज्यपाल को एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा है जो बहुस्तरीय व्यवस्था के दो स्तरों को जोड़ती है, न कि उन्हें विभाजित करती है। अलबत्ता अब न्यायालय की राय यह भी दर्शाती है कि उसकी भूमिका ‘स्पष्ट परिस्थितियों’ तक सीमित है।

अब अदालत ने अपनी सलाह में कहा है कि राज्यपालों की तथाकथित ‘निष्क्रियता’ के बावजूद, ‘संवैधानिक न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेक और विचारों का स्थान नहीं ले सकते।’ तमिलनाडु विधानसभा से पास होने के बावजूद दस विधेयकों को रोक कर रखने के राज्यपाल आरएन रवि के फैसले को अवैध करार देते हुए अप्रैल में उच्चतम न्यायालय ने एक संवैधानिक पेच को खोल ज़रूर कर दिया, पर इससे केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यपालों की भूमिका से जुड़ी पहेलियों का हल पूरी तरह नहीं हुआ था।

हाल के वर्षों में कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य विधान परिषदों में नामांकन और राज्यपाल द्वारा पारंपरिक अभिभाषण के संपादन या सदन को बुलाने पर दुर्भाग्यपूर्ण रस्साकशी तो हुई ही है, विधानमंडलों से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी या इनकार जैसे कार्य भी हुए हैं। तमिलनाडु, केरल और बंगाल में सरकारों और राज्यपालों के बीच ऐसे कई विवाद खड़े हुए हैं। विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के अप्रैल के फैसले ने उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया था। इस निर्णय का महत्व तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा से कहीं अधिक था।

अप्रैल में न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को ‘शीघ्रता से काम करना चाहिए’ और किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर वे ‘पॉकेट वीटो’ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 200 को अनुच्छेद 163 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य करता है। यदि कैबिनेट की सलाह के विपरीत राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या उसे सुरक्षित रखते हैं, तो उन्हें ऐसा तीन महीने के भीतर करना होगा। दोबारा पारित विधेयकों के लिए समय-सीमा घटाकर एक महीना कर दी गई।

तमिलनाडु सरकार ने शनिवार, 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से छूट देने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी न दिए जाने के फैसले को फिर चुनौती दी है। ‘नीट’ से छूट हासिल करना राज्य के दशकों पुराने नीतिगत विमर्श का फिलहाल अनिर्णीत अध्याय है। केंद्रीय नीति के खिलाफ राज्य का कानून बनाने का इतना लंबा कोई अन्य प्रयास नहीं रहा है। सितंबर 2017 में, ‘नीट’ विरोधी दो विधेयकों का राष्ट्रपति भवन में यही हश्र हुआ। चार साल बाद, सत्तारूढ़ डीएमके ने, ‘नीट’ से छूट को अपना चुनावी वायदा बनाया। सरकार बनाने के बाद जस्टिस एके रंजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में 2021 में विधेयक पारित किया। उसे स्वीकृति नहीं मिली, जिसे लेकर सरकार अब फिर सुप्रीम कोर्ट गई है।

-लेखक वरिष्ठ संपादक रहे हैं।

नक्सली तो मर ही रहा, मगर नक्सलवाद फिर भी जिंदा

जयसिंह रावत

भारत में सुरक्षा बलों की लगातार सफल कार्रवाइयों ने माओवादी उग्रवाद को अब तक के सबसे कमजोर मुकाम पर पहुंचा दिया है। शीर्ष कमांडरों के सफाए, बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण और दबाव बढ़ने के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि नक्सलवाद का ग्राफ नीचे जा रहा है। परंतु यह केवल सैन्य उपलब्धियों का प्रश्न नहीं है; इसकी जड़ें उन असमानताओं में हैं जिन्हें मिटाए बिना इस आंदोलन का पुनर्जीवन किसी भी समय संभव है। जंगलों में बंदूकें शांत होंगी तभी जब लोगों के भीतर जमीं असंतुष्टि भी शांत होगी।

सरकार ने 2026 तक देश को पूरी तरह नक्सलवाद-मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और हालिया आंकड़े बताते हैं कि यह लक्ष्य अब पहले की तुलना में अधिक यथार्थवादी लगने लगा है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2014 से सितंबर 2025 तक देशभर में 8,751 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1,801 मारे गए। इसी अवधि में 5,000 से अधिक हथियार बरामद किए गए, जिनमें राइफलें, विस्फोटक और संचार उपकरण शामिल हैं। 2025 में सुरक्षा बलों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मई में छत्तीसगढ़ में [illegible] (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू एक बड़ी कार्रवाई में मारे गए।

इसके बाद नवंबर में माओवादी सैन्य गतिविधियों का संचालन करने वाले मदवी हिंडमा के मारे जाने ने उनकी कमान व्यवस्था को गहरा झटका दिया। अकेले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वर्ष 2025 में 144 माओवादी या तो मारे गए, या गिरफ्तार हुए अथवा आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए। एक दशक पहले 76 जिलों में फैला रेड कॉरिडोर अब सिमटकर केवल 11 जिलों तक रह गया है। इनमें तीन जिले—सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर—अब भी सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी सीमाओं से माओवाद को लगभग पूरी तरह बेदखल कर दिया है और उग्रवादी गतिविधियाँ वहाँ प्रतीकात्मक रह गई हैं। इस वर्ष लगभग 270 माओवादी ढेर किए गए और दर्जनों गिरफ्तार हुए।

नक्सलवाद केवल विचारधारा का प्रश्न नहीं था। 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से निकली इस लपट को हवा मिली थी विस्थापन, भूमि-अधिकारों के हनन और विकास योजनाओं में उपेक्षा ने। खनन, बांध और उद्योगों के विस्तार ने हजारों परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल किया और न्याय तक पहुंच की कमी ने उनके भीतर गहरी पीड़ा और असंतोष पैदा किया।

इस असंतोष ने कई क्षेत्रों में माओवादी नेटवर्क को फलने-फूलने में मदद की। आज भी हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं। 2025 में ही नक्सल हिंसा के चलते 255 लोगों की जान गई। इनमें निर्दोष ग्रामीणों की मौतें भी शामिल थीं, जिन्होंने सुरक्षा अभियानों को उपेक्षा और भय से जोड़ दिया। अनेक मानवाधिकार संगठन चेतावनी देते हैं कि यदि नागरिकों की सुरक्षा, न्याय और सम्मान सुनिश्चित नहीं हुआ, तो दबा हुआ असंतोष फिर किसी नई शक्ल में फूट सकता है।

नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई अब केवल बंदूकों तक सीमित नहीं रह सकती। विकास-आधारित पहलकदमियों के बिना स्थायी समाधान अधूरा है। केंद्र ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए बजट में भारी वृद्धि की है और सैकड़ों नए सुरक्षा कैंप तथा हेलिपैड बनाए हैं, जिससे प्रशासन की पहुंच बढ़ी है। लेकिन केवल सुरक्षा ढांचा खड़ा कर देना पर्याप्त नहीं है; इन इलाकों में जीवनस्तर सुधारना सबसे अधिक आवश्यक है। दूरस्थ गांवों में अब भी स्कूल अधूरे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, सड़कें बरसात में धंस जाती हैं और नौकरियों के अवसर लगभग नदारद हैं। अदालतें और प्रशासनिक दफ्तर कई-कई घंटे दूर हैं। आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ सुधार लाया है, पर क्रियान्वयन में सुस्ती और भ्रष्टाचार अभी भी बड़ी बाधाएं हैं।

चुनौती अब भी बाकी

नक्सलवाद की कमर टूट रही हैं, लेकिन उसकी जड़ें अभी जीवित हैं। यह विद्रोह अक्सर मृत नहीं होता, बल्कि अवसर मिले तो फिर उठ खड़ा होता है। यदि विकास कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार, अविश्वास या उपेक्षा बढ़ी, तो यह जोंबी विद्रोह किसी भी समय फिर से सक्रिय हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ विशेषज्ञ समय-समय पर चेताते रहे हैं कि गोलियाँ केवल समय खरीदती हैं; स्थायी समाधान न्याय और विकास से आता है।

- यह लेखक के अपने विचार हैं।

एआई से मुकाबले के लिए जरूरी मानवीय क्षमताएं

डॉ शशांक द्विवेदी

आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन, कामकाज और सोचने के तरीके को बदल रही है। एआई आज हर क्षेत्र—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, मीडिया—में अपनी पैठ बना चुकी है। जहां एक ओर यह तकनीक कार्यक्षमता बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर यह चिंता भी बढ़ा रही है कि भविष्य में क्या मनुष्य के रोजगार छिन जाएंगे?

यह सवाल बेहद प्रासंगिक है। क्या इंसान एआई से मुकाबला कर पाएगा? जवाब है—हां, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी क्षमताएं विकसित करें जिनकी बराबरी एआई कभी नहीं कर सके।

एआई तेज़ी से डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, और जटिल निर्णय भी ले सकता है। लेकिन यह एक सच्चाई है कि एआई में मानवीय भावनाएं, नैतिकता, रचनात्मकता और सहानुभूति नहीं होती। एआई ‘सोचता’ नहीं, बल्कि ‘सीखाए गए पैटर्न’ पर काम करता है। यह वही कर सकता है जो उसे सिखाया गया है; नई परिस्थितियों में मानवीय समझ या संवेदनशीलता नहीं दिखा सकता। इसलिए, भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो अपनी मानवीय क्षमताओं को निखारेंगे और तकनीक को अपना सहयोगी बनाएंगे, प्रतिस्पर्धी नहीं। एआई से आगे रहने के लिए विकसित की जाने वाली मुख्य क्षमताएं मानवीय पूंजी है।

एआई के पास भावनाएं नहीं हैं, लेकिन इंसानों के पास यह सबसे बड़ी ताकत है। नेतृत्व, टीम वर्क, ग्राहक सेवा, या लोगों के साथ जुड़ने की क्षमता—ये सब भावनात्मक समझ से ही संभव हैं। अपनी सहानुभूति, संवाद शैली और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को बढ़ाएं। भविष्य में जो व्यक्ति ‘लोगों को समझना’ जानता है, वही ‘मशीनों को चलाना’ भी बेहतर कर पाएगा।

रचनात्मक सोच वह क्षेत्र है जहां एआई अभी भी पीछे है। एआई मौजूदा डेटा के आधार पर सुझाव देता है, लेकिन नई और मौलिक अवधारणा गढ़ने की क्षमता केवल मनुष्य के पास है। कलाकार, डिजाइनर, लेखक, उद्यमी और इनोवेटर—इन सभी को भविष्य में बड़ा स्थान मिलेगा।

रचनात्मक सोच का अभ्यास करें: पेंटिंग, कहानी लेखन, संगीत, डिजाइन थिंकिंग या किसी समस्या के नए समाधान निकालना। सिर्फ़ जानकारी याद कर लेना काफी नहीं है। ज़रूरी है सवाल करना, ‘ये बात सच में सही है या नहीं? इसके पीछे कौन-सी धारणाएं छिपी हैं? इसका दूसरा पहलू क्या है?’ मशीन आपको बहुत जवाब दे सकती है, लेकिन सही को चुनना और गहराई से समझना इंसान ही कर सकता है।

आपके सामने कोई अख़बार की ख़बर आती है कि ‘यह दवा हर बीमारी का इलाज है।’ मशीन उस खबर को हज़ारों तरीकों से कॉपी कर सकती है, लेकिन एक इंसान ही यह सवाल पूछ सकता है, ‘क्या यह सच है? इसके पीछे किसका लाभ छिपा है? क्या इसके प्रमाण हैं?’ जैसे किसी समझदार किसान की तरह, जो बीज बोने से पहले मिट्टी को परखता है। वह आंख बंद करके नहीं बोता। उसी तरह, सोचने वाला इंसान भी हर बात को परखता है। यही आदत आपको धोखे से बचाती है और सच्चाई तक ले जाती है।

जिम्मेदार और अनुशासन आदत है अपने वचन निभाने की। वह काम पूरा करना जो आपने तय किया, चाहे मन न हो, चाहे थकान हो। मशीन को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान जब मुश्किल होने पर भी टिकता है, तभी असली ताक़त पैदा होती है। थॉमस एडिसन, बल्ब बनाने वाला वैज्ञानिक, उसने हज़ारों बार प्रयोग किया और असफल हुआ। अगर वह बीच में छोड़ देते तो आज अंधेरा ही रहता।

एआई किसी समस्या का समाधान डेटा के आधार पर करता है, लेकिन जटिल मानवीय या सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल इंसान ही सोच सकता है। ‘क्यों’, ‘कैसे’ और ‘क्या’ पूछने की आदत डालें। समस्या को देखने के कई दृष्टिकोण अपनाएं और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करें।

तकनीक तेजी से बदल रही है, इसलिए ‘सीखते रहना’ ही भविष्य का सबसे बड़ा हथियार है। नई तकनीकों, टूल्स और ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेट रखें। अगर आप एक कौशल में विशेषज्ञ हैं, तो उससे जुड़े नए क्षेत्रों में भी ज्ञान बढ़ाएं।

एआई के प्रयोग के साथ कई नैतिक सवाल भी उठते हैं—डेटा गोपनीयता, फेक न्यूज, साइबर सुरक्षा आदि। भविष्य में वे पेशेवर मूल्यवान होंगे जो तकनीक के साथ-साथ उसकी नैतिक सीमाओं को भी समझेंगे। समाज के लिए जिम्मेदार तकनीकी उपयोग की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए, भविष्य में आपको मशीन से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। वह तो हमेशा तेज़ रहेगी। आपको इंसानियत को संभालना है,स्पष्ट सोच, मज़बूत चरित्र, सच लिखने-बोलने की हिम्मत, बातचीत और समझौते की कला, और दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति। यही असली ताक़त है, यही गुण कभी भी बदले नहीं जा सकते।

भविष्य में एआई के दौर में असली ताक़त उन लोगों के पास होगी, जिनके पास ये मानवीय गुण होंगे। मसरल, सवाल पूछने की हिम्मत, कठिनाई में टिके रहने का अनुशासन, अपने विचारों को लिखकर स्पष्ट करने की कला, भरोसे से बातचीत करने की क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने का नेतृत्व। यही वह रास्ता है जिससे इंसान हमेशा मशीन से आगे रहेगा।

- लेखक विज्ञान विषयों के जानकार हैं।

मन का दर्पण

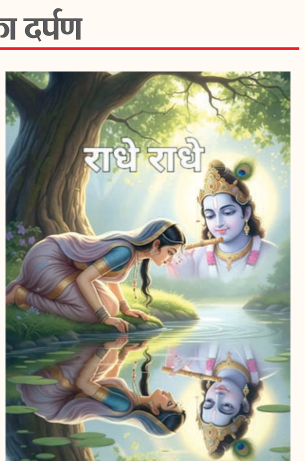

दर्पण में देख छाया, छरहरी
गोरी काया,
आनंद विभोर प्यारी,
शोभा सुकुमारी रे।

नयन कटारी कोर, आर-
पार ओर-छोर,
होठ लगे मधुशाला,
आँखे कजरारी रे।

मन का दर्पण साफ, पास
रखो सदा आप,
भावना पवित्र मन,
जाऊँ बलिहारी रे।

‘सुषमा’ सुंदर छटा,
घुँघराले केश घटा,
मुख पर लट झूले,
रूप मनोहारी रे।

कवयित्री
सुषमा प्रेम पटेल
रायपुर छत्तीसगढ़

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

JITU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली बेंगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रानिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ

भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

खास खबर

स्कूल शिक्षा मंत्री यादव ने किया अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण

दुर्ग। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने शुक्रवार को लगभग 144.78 लाख रुपये की लागत से निर्मित रविशंकर स्टेडियम के समीप अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। मंत्री यादव ने फीता काटकर इस नवीन खेल परिसर को जनता को समर्पित किया। स्कूल शिक्षा मंत्री यादव ने कहा कि यह अत्याधुनिक इंडोर सुविधा न केवल युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए उपयुक्त वातावरण देगी, बल्कि जिले में खेल को नई दिशा देने और युवा प्रतिभाओं को सशक्त मंच उपलब्ध कराने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से आने वाली पीढ़ियों को स्थायी लाभ मिलेगा। अब जिले के खिलाड़ी रात्रिकालीन अभ्यास के साथ बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। लोकार्पण के पश्चात मंत्री गजेन्द्र यादव और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में रैकेट थामकर बैडमिंटन भी खेला। दोनों ने शॉट लगाकर कोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं का अनुभव लिया, जिसे उपस्थित खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों ने सराहा।

समर्थन मूल्य में बढोत्तरी ने गजल यादव को बनाया सफल 'टेक्नो-फार्मर'

दुर्ग। दुर्ग जिले के ग्राम बोरई से आने वाले किसान-इंजीनियर गजल यादव की कहानी कई युवाओं और किसानों के लिए प्रेरणा है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद, गजल ने कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपने पैतृक व्यवसाय कृषि को चुना। उन्होंने पारंपरिक कृषि में इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को मिलाकर 'टेक्नो-फार्मिंग' का सफल प्रयोग किया। गजल बताते हैं कि मेरी पढ़ाई ने खेती को एक वैज्ञानिक नज़रिया दिया। इंजीनियरिंग से मैने डेटा एनालिटिक्स सीखा, जिसका इस्तेमाल करके मैंने मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम के सटीक डेटा के आधार पर बीज, खाद और पानी का उपयोग किया और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उनकी इनपुट लागत को बहुत कम कर दिया। लेकिन मेरी मेहनत को असली पहचान तब मिली, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल का ऐतिहासिक समर्थन मूल्य घोषित किया। यह दर देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया गया अब तक का सर्वाधिक औपचारिक मूल्य है।

बाल विवाह मुक्त अभियान को गति देने संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रेरणा सभाकक्ष में संभाग स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संभागायुक्त एस.एन. राठौर और महापौर अलका बाघमार शामिल हुए। कार्यशाला में दुर्ग संभाग के छह जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत और श्रम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संभागायुक्त राठौर ने जिलों से आए अधिकारियों से बाल विवाह की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि जिलों में बाल विवाह के मामलों की संख्या शून्य है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राठौर ने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन

अपराध है बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या भी है। उन्होंने यह भी बताया कि कम उम्र में विवाह होने से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकार प्रभावित होते हैं, साथ ही कुपोषण और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह की सूचना देने के प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा कि यदि पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर सभी विभाग सजग रहें, तो बाल विवाह को पूरी तरह रोका जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों को बाल विवाह के विरुद्ध हर संभव प्रयास करने तथा परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी भी बालिका का बाल विवाह न होने देने की शपथ दिलाई।

महापौर अलका बाघमार ने भी जनभागीदारी की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि समाज के सहयोग से ही बाल विवाह को रोकने में सफलता मिल सकती है। उन्होंने सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने और नोनी सुरक्षा योजना व सुकन्या योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता बताई।

शिक्षा मंत्री यादव ने व्यवहारिक कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल

नई शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा चुनौती एवं संभावनाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) दुर्ग में ' 'नई शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा चुनौती एवं संभावनाएं'' विषय पर 18 एवं 19 नवम्बर को संकुल समन्वयकों की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला के समापन अवसर पर गजेन्द्र यादव, मंत्री, स्कूल शिक्षा विधि एवं विधायी, ग्रामोद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित हुए। इस दौरान मंत्री यादव ने व्यवहारिक कौशल के प्रति जागरूकता एवं सफलता से सीखने की क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया।

उल्लेखनीय है कि संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर के निर्देशानुसार एवं प्राचार्य पी सी मरकले डाइट दुर्ग अछोटी के मार्गदर्शन में यह कार्यशाला रखी गई थी। पहले दिन उद्घाटन सत्र में प्राचार्य पी.सी. मरकले ने कौशल अंतराल में कम करने की बात कहीं।

विशिष्ट वक्ता आईआईटी भिलाई से डॉ. गगन राज गुप्ता सह प्राध्यापक एवं उनके सहयोगी निकेत ने वर्तमान

आवश्यकता के अनुरूप कौशल के उन्नयन पर जोर दिया। कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंस से डॉ. सारंग पोपली, सहा. प्राध्यापक, कामधेनु वि.वि. ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसरों पर बात की।

संकाय सदस्य सत्येन्द्र शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में दुर्ग संभाग से डाइट खैरागढ़, कवर्धा, बेमेतरा व बी टी आई डोंगरगांव से दो-दो प्रतिभागी एवं बालोद जिला के बालोद, गुंडरदेही, गुरूर, डौंडीलोहारा और डौंडी विकासखंड से कुल 25 संकुल स्त्रोत समन्वयक (सीएसी) एवं दुर्ग, पाटन, धमधा से 15 सीएसी और गत वर्ष हाई व हायर सेकेंडरी विद्यालय के व्याख्याताओं को ट्रेनिंग देने वाले 24 मास्टर ट्रेनर को कार्यशाला में बुलाया गया था।

इस दौरान डाइट खैरागढ़, बीटीआई डोंगरगांव एवं डाइट दुर्ग के अकादमिक सदस्यों ने शोध आलेखों की प्रस्तुति दी। बीटीआई डोंगरगांव से डी.एल.एड. के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा के सर्वेक्षण पर सराहनीय शोध आलेख प्रस्तुत किया। डाइट खैरागढ़ से रचना दत्त एवं डॉ. मकसूद ने व्यावसायिक शिक्षा की चुनौतियों के लिए समाधान सुझाए।

डाइट दुर्ग से डॉ. भट्टाचार्य ने व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में जोड़ने के विषय में विचार रखा। कार्यशाला के दूसरे दिन विशिष्ट वक्ता सुनील मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षक, एससीईआरटी ने व्यावसायिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता' पर व्याख्यान दिया। सेजेस खुर्सीपार की व्याख्याता नादिरा यास्मीन ने डेयरी उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिशिर भट्टाचार्य ने व्यावसायिक शिक्षा नई शिक्षा के संदर्भ में पुर्नचिंतन पर सहज रूप से अपनी प्रस्तुति दी। समापन अवसर पर डाइट की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक संध्या शर्मा ने अभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. चंदना सिंह ने किया।

आयुक्त ने उद्यानों और प्रस्तावित व निर्मित डोम शेडों का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पहल के तहत, निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को जोन-5 के सेक्टर-6 अंतर्गत विभिन्न उद्यानों और प्रस्तावित व निर्मित डोम शेडों का औचक निरीक्षण किया। निगम आयुक्त के साथ जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे भी उपस्थित रहे। उन्होंने सेक्टर-6 के अंतर्गत सड़क 67 उद्यान, धोबी घाट स्थित उद्यान और मार्केट के हनुमान मंदिर समीप गार्डन का गहन निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने उद्यानों की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किया कि इन स्थानों की व्यवस्था को तत्काल सुधारकर नियमित रूप से साफ-सुथरा रखा जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दुर्गा मंच के समीप बने डोम शेड और डी मार्केट के पीछे प्रस्तावित डोम शेड स्थल का भी अवलोकन किया। प्रस्तावित स्थल पर कार्य शीघ्रता से प्रारंभ करने के निर्देश उप अभियंता श्वेता महेश्वर को दिए गए। भ्रमण के दौरान निगम आयुक्त ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। इस दौरान कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा उद्यान की फेसिंग पर कपड़े सुखाए जा रहे थे, जिस पर आयुक्त ने उन्हें समझाते हुए उद्यान के नियमों का पालन करने और फेसिंग पर कपड़े न सुखाने की हिदायत दी। निगम आयुक्त ने कहा कि भिलाई को सुंदर और हरा-भरा बनाए रखने के लिए यह निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेगा।

संभाग आयुक्त ने धान उपार्जन केन्द्र अण्डा व कुथरेल का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने शुक्रवार को धान उपार्जन केन्द्र अण्डा और कुथरेल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां अब तक की धान खरीदी, केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं, बारदाने, धान की नमी, स्टेग आदि की जानकारी ली और मौके पर उपस्थित समिति प्रबंधक को आश्वयक दिशा निर्देश दिये। संभाग आयुक्त राठौर उपार्जन केन्द्र में धान बेचने पहुंचे किसानों से रू-ब-रू चर्चा कर धान की पैदावारी और खरीदी हेतु सरकार की व्यवस्था की जानकारी ली।

कृषकों ने बताया कि सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति पश्चात् केन्द्रों में मौजूदगी और कार्य सम्हालने से धान खरीदी कार्य में तेजी आई है। उन्होंने सरकार की पारदर्शी व्यवस्था की सराहना किये। उपार्जन

केन्द्र प्रभारी ने बताया कि अण्डा उपार्जन केन्द्र में अब तक 4986.40 क्विंटल धान खरीदी हुई है। जिसमें मोटा धान की मात्रा 735.20 क्विंटल, पतला धान 3007.60 क्विंटल और सरना धान 1243.60 क्विंटल शामिल है। उपार्जन केन्द्र से 75 किसान लाभान्वित हुए। इसी प्रकार कुथरेल उपार्जन केन्द्र में अब तक 2686.00 क्विंटल धान खरीदी की गई है। जिसमें धान मोटा 140.00 क्विंटल, धान पतला 968.40 क्विंटल और सरना 1577.60 क्विंटल शामिल है। उपार्जन केन्द्र से 62 किसान धान बेच कर लाभान्वित हुए है।

अवैध होर्डिंग्स हटाने में निगम की सख्ती, सुपेला क्षेत्र में ओवर ब्रिज पिलर्स से हटाए गए विज्ञापन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देशानुसार, निगम क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए प्रचार सामग्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जोन क्रमांक 01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17, सुपेला के घड़ी चौक से चंद्रा मौर्या तक ओवर ब्रिज के पिलर्स पर केंद्रित थी।

इस क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर को हटाने का अभियान चलाया गया।

ओवर ब्रिज के पिलर्स पर लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के सभी अवैध

विज्ञापन सामग्री को हटाया गया, जिससे सार्वजनिक सौंदर्य और यातायात सुरक्षा में सुधार हुआ। अवैध विज्ञापन लगाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। कुल चालानी कार्यवाही 1500 रुपए का किया गया है। जिसमें इंटीरियल पोस्टर्स रमन सिंह से 500 रुपए, सुधीर एक्सरे से 1000 रुपए चालानी कार्यवाही की गई है। संबंधित प्रतिष्ठानों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध बैनर, पोस्टर या होर्डिंग का उपयोग न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने में स्वच्छता विभाग एवं राजस्व टीम का विशेष योगदान है।

कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी प्रसून तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह, क्रिस्टोफर पॉल एवं जी प्रमोद उपस्थित रहे।

निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापन सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

21वीं किश्त जारी किये जाने पर पीएम किसान दिवस का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत 19 नवम्बर 2025 को ''किसान सम्मान समारोह'' का आयोजन कर वाराणसी उत्तर प्रदेश से 21वीं किश्त की राशि प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश में किया गया, जिले में कार्यक्रम का आयोजन जिला, विकासखण्ड, सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत पर आयोजन किया गया।

जिले में मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा एवं पाहंदा (अ) में किया गया। उक्त कार्यक्रम में ''पी.एम. किसान दिवस'' के रूप में प्रधानमंत्री के उद्बोधन का प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र अंजोरा में मुख्य अतिथि संगीता साहू सरपंच ग्राम पंचायत अंजोरा (ख), डॉ. आर.आर.बी. सिंह कुलपति, डॉ. संजय साक्य निदेशक विस्तार सेवाएं दाऊ वासूदेव कामधेनू विश्वविद्यालय, संदीप कुमार भोई उप संचालक कृषि, डॉ. विकास

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

खुंणे प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र सुचित्रा दरबारी सहायक संचालक कृषि, वैज्ञानिकगण,कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में समस्त जनों ने प्रधानमंत्री के किसानों के नाम संदेश को ध्यानपूर्वक सुना एवं इस कार्यक्रम के तहत डी.बी.टी. के माध्यम से 2000 रूपए की 21वीं किश्त जारी करने की प्रक्रिया को देखा। इसके तहत जिले के 78859 कृषकों को 21वीं किश्त की राशि रु 15.77 करोड़ जारी की गई। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों से सीधा संवाद कर खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा धान के साथ अन्य फसलों को भी लगाने तथा खाद्यान्न के साथ दलहन-तिलहन इत्यादि क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की गई। साथ ही किसानों को जैविक खेती, बीजोपचार, पोषक तत्व प्रबंधन तथा डी.ए.पी. के वैकल्पिक उर्वरक नैनो डी.ए.पी. इत्यादि के लिए मार्गदर्शन किया गया है।

कई किसानों ने इस योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती में उपयोगी बताते हुये अभार व्यक्त किया उनका कहना है कि इस योजना से उन्हे बीज, खाद एवं अन्य कृषि कार्यो के लिए समय पर सहायता मिलती है जिससे उनकी उत्पादकता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई।

27,590.12 मेट्रिक टन धान की खरीदी

दुर्ग। दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत सभी 102 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की जा रही है। सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति पश्चात् समितियों एवं उपार्जन केन्द्रों में मौजूदगी से जिले में धान खरीदी प्रक्रिया रफ्तार पकड़ ली है। जिले के पंजीकृत 112446 किसानों से 6,16435 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

ग्राम पंचायतों के सुव्यवस्थित कार्यालय ग्रामीणों की बढ़ती सहूलियतें

रायपुर। ग्राम पंचायत की बेहतर कार्यप्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यालय भवन अत्यंत आवश्यक होता है। यह न सिर्फ पंचायत व्यवस्था का केंद्र है, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। कोरिया जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए ग्रामीण अधोसंरचना विकास को नई गति दी है। मनरेगा ने अकुशल श्रम को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका में स्थायी सुधार लाने का रास्ता खोला है। अधोसंरचनाओं के विकास में यह योजना अब ग्रामीण प्रगति की रीढ़ बन चुकी है। इसी प्रयास का परिणाम है कि जनपद पंचायत सोनहत और बैकुण्ठपुर में पिछले एक दशक में 45 नए ग्राम पंचायत कार्यालय भवन बनाए गए हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हुई है और ग्रामीणों को सुविधाएं और आसानी से मिलने लगी हैं। नए निर्मित कार्यालय भवनों में जनप्रतिनिधियों, सचिव और रोजगार सहायक के लिए अलग कक्ष, बैठकों और ग्राम सभा संचालित करने की व्यवस्था, दस्तावेजों के संधारण की सुरक्षित सुविधा है। इन व्यवस्थाओं से ग्रामीणों के कार्य समय पर निपट रहे हैं, संवाद बेहतर हुआ है और पंचायत स्तर पर कार्यशैली अधिक पारदर्शी व सुगम बनी है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत कोरिया जिले में कुल 45 नए ग्राम पंचायत कार्यालय भवन निर्मित किए गए हैं। सोनहत व बैकुंठपुर जनपद पंचायत में 45 भवन, 5 करोड़ 96 लाख रूपए से अधिक की लागत से तैयार की गई है। सभी निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए गए, जिससे गुणवत्ता, स्थानीय सहभागिता और लागत की पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

सर्कुलर ईकोनॉमी एवं वेस्ट मैनेजमेंट पर संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के तत्वाधान में भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल सर्कुलर ईकोनॉमी एवं वेस्ट मैनेजमेंट (Waste to Wealth) विषय पर बिलासपुर संभाग के लिए एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम प्लेनेटेरियम, व्यापार विहार, बिलासपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के सदस्य सचिव आर. अगसिमनी ने की। कार्यक्रम की रूपरेखा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुरेश चंद ने प्रस्तुत की, वहीं स्वागत उद्बोधन क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। कार्यशाला में सर्कुलर ईकोनॉमी व वेस्ट मैनेजमेंट के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंडल मुख्यालय रायपुर के मुख्य रसायनज्ञ श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव ने उद्योग प्रतिनिधियों को वेस्ट टू वेल्थ, ईपीआर (E&tended Producer Responsibility) एवं इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर के मुख्य रसायनज्ञ सूरज कुमार धुर्वे ने फ्लाई ऐश मैनेजमेंट तथा MOEF की अधिसूचनाओं एवं दिशानिर्देशों पर उपयोगी जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि, ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, टायर वेस्ट व यूज़्ड ऑयल रिसायकलर उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में स्थापित एकमात्र टीएसडीएफ मेसर्स केसदा वेस्ट मैनेजमेंट द्वार AFR तकनीक की जानकारी दी गई। राहुल झा ने ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग एवं क्रिटिकल मिनरल रिकवरी पर प्रस्तुति दी। एनटीपीसी सीपत, बिलासपुर के पंकज शर्मा तथा एनटीपीसी लारा, रायगढ़ के डॉ. सुधीर दहिया ने फ्लाई ऐश के पर्यावरण-अनुकूल उपयोग के उदाहरण और उपलब्धियों को साझा किया। कार्यशाला के समापन अवसर पर सदस्य सचिव आर. अगसिमनी ने उद्योगों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और आश्वस्त किया कि मंडल सर्कुलर ईकोनॉमी व ईपीआर से संबंधित औद्योगिक आवेदनों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा, जिससे उद्योगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

मत्स्य किसानों को आर्थिक समृद्धि हेतु नवीन तकनीक एवं कौशल विकास को अपनाने की जरूरतः मंत्री नेताम

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा मछलीपालन मंत्री रामविचान नेताम विश्व मात्स्यिकी दिवस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषि मंडपम सभागार में आयोजित एक दिवसीय मत्स्य कृषक संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रति वर्ष 21 नवंबर को विश्व मात्स्की दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन के महत्व, मछुआ समुदाय के अधिकारों, आर्थिक आजिविका, खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत एवं समुदाय सशक्तिकरण हेतु जागरूकता लाना है। नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रजत जयंती मना रहा है। राज्य में प्राकृतिक रूप से मछली पालन के स्त्रोत प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। मत्स्य किसानों के विकास के लिए आवश्यकता है केवल नवीन तकनीक, मानव कौशल विकास, आर्थिक प्रोत्साहन एवं सहायता की।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने बताया कि शासन ने राज्य निर्माण के पश्चात राज्य एवं केन्द्र की विभिन्न योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील काति, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि के माध्यम से मछली पालन विकास के सतत् प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में कुल 1,30,001 जल स्त्रोत (2.039 लाख हेक्टेयर) उपलब्ध है जिनमें 98 प्रतिशत् में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। 3571 किलोमीटर का नदीय जलक्षेत्र भी उपलब्ध है। सघन मत्स्य पालन हेतु अतिरिक्त जलक्षेत्र निर्मित किया जा रहा है, अब तक कुल 7580 हेक्टर जलक्षेत्र निजी क्षेत्र में अतिरिक्त निर्मित हो चुका है।

मछली पालन हेतु गुणतत्ता युक्त मत्स्य बीज एक आधारभूत आवश्यकता है। राज्य को मत्स्य बीज के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु निरंतर प्रयास जारी है। अब तक कुल 82 नवीन हैचरी निर्मित कर 120 हैचरियों के माध्यम से 583 करोड़ मत्स्य बीज प्रति वर्ष उत्पादित हो रहा है, एवं राज्य देश में 6 वें स्थान पर है। हमारा राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ अपितु अन्य राज्यों को निर्यात भी हो रहा है।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जांजगीर में थोक मत्स्य बाजार की स्थापना

मंत्री नेताम ने कहा कि विपणन व्यवस्था को सुदृढ बनाने एवं उपभोक्ता तक ताजी मछली पहुंचाने के लिए 1008 मोटर साइकल, आईस बॉक्स, 10 थी व्हीलर एवं 05 इन्सुलेटेड ट्रक, 114 वाहन (लाइव फिश वेडिंग सेन्टर) वितरित किए गए।

रायपुर दुर्ग बिलासपुर एवं जांजगीर में थोक मत्स्य बाजार की स्थापना की गई। मंत्री नेताम ने इस मौके पर मछुआ संघ की ओर से हितग्राहियों को लाभांश राशि का चेक प्रदान किया।

मत्स्य पालन बेरोजगारी दूर करने का सशक्त साधन

कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा और रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने भी सम्बोधित किया। मछलीपालन पालन विभाग के संचालक एमएस नाग ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि भारत के मध्यस्थल पर स्थित प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछलीपालन हेतु उपयुक्त है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त साधन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को मछलीपालन की आधुनिक तकनीकी पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1840 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से 63 हजार 280 सदस्य मत्स्य पालन कर रहे हैं। संगोष्ठी में मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉ. लखन लाल धीवर, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद, मछुआ कल्याण बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष बसंत तारख और रामकृष्ण धीवर सहित बड़ी संख्या में मत्स्य किसान शामिल थे।

पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता

फोर्टिफाइड चावल के उपभोग से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने से मिलेगा लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य शासन कुपोषण से लड़ने और राज्य में फोर्टिफ इड चावल के उपभोग को बढ़ावा देने निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और समाज कल्याण फाउंडेशन के सहयोग से गत दिवस मेफेयर लेक रिज़ॉर्ट, रायपुर में चावल फोर्टिफिकेशन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ष्पोषण प्रथम् जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है।

रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की निदेशक डॉ. फरिहा आलम ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की तकनीकी सहायता से विभाग चावल फोर्टिफिकेशन पर नवंबर 2020 से कार्य कर रहा है और अब इसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आम जन फोर्टिफाइड चावल के उपभोग के महत्व को समझने लगे हैं। यह कार्यशाला प्रतिभागियों को फील्ड स्तर के प्रश्नों को जानने-समझने और फोर्टिफाइड चावल के उपभोग से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होगी।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की सहायक प्राध्यापक डॉ. शुभा बनर्जी ने कार्यशाला में चावल फोर्टिफिकेशन की ष्क्या, क्यों, कहाँ, कैसे और कब पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में एनीमिया की उच्च दर अपर्याप्त पोषण का परिणाम है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति और खपत भी एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत एनिमिया दूर करने की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है और इससे एनीमिया में कमी आयी है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के सीनियर प्रोग्राम एसोसिएट अरुणांशु गुहाठकुरता ने छत्तीसगढ़ में चावल फोर्टिफिकेशन पर डब्लूएफपी की भूमिका पर जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम के विकास, तकनीकी सहायता इकाई इकाई की स्थापना और फोर्टिफाइड चावल के उपयोग के संबंध में जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप संचालक एवं बाल स्वास्थ्य एवं नोडल अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत, ने बताया कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में विभाग का प्राथमिक फोकस आईएफए सप्लीमेंटेशन प्रदान करना है। खाद्य विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल शुरू करने की पहल अत्यंत सराहनीय है, जिससे एनीमिया में कमी आई है। कार्यशाला के बाद प्रतिभागियों की जिम्मेदारी होगी कि वे सीखी हुई बातों को समुदाय स्तर पर ले जाएँ और फोर्टिफाइड चावल के उपभोग को बढ़ावा देने तथा मिथकों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करें।

कार्यशाला में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रमुख डॉ. सारिका यूनुस ने विभिन्न राज्यों के सफल केस स्टडी की जानकारी दी। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञो की पैनल चर्चा भी आयोजित की गई जिसमें फोर्टिफाइड चावल से जुड़े विभिन्न मिथकों एवं भ्रांतियों पर चर्चा की।

ग्रीष्मकालीन धान की जगह अब गेहूं, चना, उड़द और मक्का की ओर किसानों का रुख

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जीपीएम जिले में कृषि विभाग रबी मौसम की खेती को बढ़ावा देते हुए किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की जगह अन्य लाभदायक फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विभाग द्वारा किसानों की बैठकों के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा रहा है और उनकी सहमति के अनुसार अनुदान पर बीज वितरण भी किया जा रहा है। उप संचालक कृषि, सत्यजीत कंवर ने बताया कि ग्रीष्मकालीन धान के लिए अत्याधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे भू-जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से बचने तथा किसानों की आमदनी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलों जैसे गेहूं, चना, उड़द और मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री कंवर ने बताया कि गुरुवार को ग्राम बारीउमराव, टंगियामार, कुदरी, कड़कई और गांजन में किसानों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इन गांवों के किसानों ने कुल 116 हेक्टेयर रकबे में ग्रीष्मकालीन धान की जगह अन्य फसलें बोने पर सहमति व्यक्त की है। कृषि विभाग की यह पहल न केवल पानी के संरक्षण में मददगार बनेगी बल्कि किसानों को स्थायी कृषि पद्धति अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता ही स्थायी खेती की दिशा में सबसे पहला कदम है।

जिले के सभी गांवों में चलेगा अभियान

कृषि विभाग द्वारा यह अभियान जिले के सभी गांवों में संचालित किया जा रहा है। ग्राम अमरपुर, पतगंवा और लटकोनी में किसानों का चयन कर लिया गया है और जल्द ही उनकी मांग के अनुसार बीज वितरण प्रारंभ किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अधिक उत्पादन, कम लागत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को एकसाथ बढ़ावा देना है।

नियद नेल्लानार योजना से बदल रही सुदूर वनांचलों की तस्वीर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नियद नेल्लानार योजना से सुकमा जिले के दूरस्थ एवं अंदरूनी गांवों में बुनियादी सुविधा और शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ आम जनता को सुलभ होने से गांवों और ग्रामीणों की तस्वीर संवरने लगी है। सुकमा जिले के दूरस्थ गांवों में कलेक्टर के मार्गदर्शन में लगातार सुविधा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन की यह पहल से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो वर्षों से मूलभूत सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से वंचित रहे थे।

सुरक्षाबलों द्वारा दो दिन पहले न्यूट्रलाइज किए गए नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पूवर्ती में भी जिला प्रशासन द्वारा बीते दिनों सुविधा शिविर लगाकर ग्रामीणों को महतारी वंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इसी दौरान पुवर्ती की निवासी मड़कम हान्दा ने शिविर में उपस्थित बीसी सखी की सहायता से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से महतारी वंदन योजना की 1000 रुपए पाकर प्रसन्नता जताई और इसके लिए शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त किया। 43 हजार रुपए की राशि निकालकर दी गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ, दुर्गम और संचारविहीन क्षेत्रों में लोगों को शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।

लखनपुर को मिला सर्व समाज मांगलिक भवन का तोहफा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नगर पंचायत लखनपुर, सरगुजा में समाज के लिए महत्वपूर्ण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का लोकार्पण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। अतिथियों का पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह मांगलिक भवन समाज की विविधता और एकता का दर्पण है। इससे क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और सर्व समाज को सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। अब इस भवन के माध्यम से बड़ी-बड़ी मांगलिक एवं सामाजिक गतिविधियां संपन्न होगी, जिससे सामाजिक समरसता और विकास को बल मिलेगा। लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने भवन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह भवन सर्व समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू ने सभी अतिथियों और जनता का आभार व्यक्त किया।

समारोह में उपस्थित लोगों ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे प्रयास समाज के विकास को नई दिशा देंगे। भवन लोकार्पण के पश्चात मंत्री अग्रवाल ने स्थानीय नागरिकों से संवाद किया और विकास योजनाओं की जानकारी दी। क्षेत्रवासियों ने मंत्री अग्रवाल सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण की पहलः वेटलैंड मित्र अभियान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण द्वारा राज्य में वेटलैंड संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र बनाने का अभियान शुरू किया गया है। वेटलैंड मित्र स्थानीय आद्रभूमियों के संरक्षण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वेटलैंड मित्र बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति त्त्क्रकोड स्कैन करके निर्धारित फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर अपने निकटतम आद्रभूमि क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। पंजीकृत वेटलैंड मित्रों को वेटलैंड संरक्षण से संबंधित जानकारी, प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही वे वेटलैंड क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की पहचान, अवैध गतिविधियों की सूचना देने तथा स्थानीय समुदाय तक आवश्यक जानकारी पहुँचाने में सहयोग करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि पूरे राज्य में अब तक 500 से अधिक वेटलैंड मित्र पंजीकृत किए जा चुके हैं। यह संख्या न केवल जन-जागरूकता के बढ़ते स्तर को दर्शाती है, बल्कि आद्रभूमि संरक्षण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करती है। वेटलैंड मित्र स्थानीय स्तर पर आद्रभूमि के स्वास्थ्य, संरक्षण गतिविधियों में भागीदारी तथा वैज्ञानिक जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कोरबा जिले में लगभग 200 वेटलैंड मित्र अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से संरक्षण कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। राज्य में जागरूक और समर्पित वेटलैंड मित्रों का मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है, जो विभाग और आम जनता के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य कर रहा है। इनके सहयोग से आद्रभूमि के जैव-विविधता मूल्य, पारिस्थितिक महत्व और सतत उपयोग की अवधारणाओं का व्यापक प्रसार हो रहा है।

वेटलैंड मित्र अभियान ने समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए राज्य की दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं को मजबूत आधार प्रदान किया है। यह पहल न केवल छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा की रक्षा कर रही है, बल्कि जनता और प्रशासन को वेटलैंड संरक्षण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महासमुंद जिले में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार

रायपुर। राज्य शासन के मंशानुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बिना किसी रुकावट के तेजी से जारी है। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज 7वां दिन हैं। जिले के 130 समितियों के 182 उपार्जन केन्द्रों में से 123 केन्द्रों में आज दिनांक तक एक लाख 44 हजार 506.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।

मैंने हार नहीं मानी', बीमारी से जूझ चुकी साउथ अभिनेत्री ने किया बॉडी ट्रांसफॉर्म तस्वीर देख हैरान हुए लोग

साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेज में गिनी जाने वाली सामंथा रुथ प्रभु ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बेहद स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड हैं। फिटनेस के प्रति उनकी दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने डेडिकेशन के साथ-साथ ट्रोल्स को भी अपने अंदाज में जवाब दे दिया।

शुक्रवार को सामंथा ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो अपने स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स दिखाती नजर आ रही थीं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा, जिसमें बताया कि कैसे कुछ साल पहले उन्हें लगता था कि शायद वह कभी फिट नहीं हो पाएंगी। लेकिन लगातार मेहनत और अनुशासन ने उनकी सोच बदल दी। आज वह अपने शरीर में आए इस बदलाव पर गर्व महसूस करती हैं और चाहती हैं कि लोग समझें- शक्ति बनाना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन की बुनियाद है।

सामंथा ने पोस्ट में क्या लिखा?

सामंथा ने अपने पोस्ट में लिखा- कुछ साल पहले तक मैंने लगभग यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरी बैक कभी मजबूत हो पाएगी। मुझे सच में लगता था कि ये मेरी जेनेटिक्स में ही नहीं है। दूसरे लोगों की शानदार बैक देखकर मैं सोचती थी- 'हां, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा।' लेकिन मैं गलत थी। और सच कहूं तो, खुश हूं कि मैं गलत थी।

ट्रोल्स को सामंथा ने दिया जवाब

सामंथा ने अपने कैप्शन में यह भी बताया कि कई दिनों तक उन्हें परिणाम नहीं दिखते थे, कई बार मन हार जाता था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उनके अनुसार, 'उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जरूरी हो जाती है। यह न सिर्फ शरीर बल्कि मानसिक ताकत भी बढ़ाती है।'

बीमारी से जूझ रही थीं सामंथा

बता दें सामंथा ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेहत को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया है। 2022 में उन्होंने खुलासा किया था कि वह मायोसिटिस नामक एक ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रही हैं, जिसमें शरीर की मांसपेशियों में सूजन और लगातार दर्द होता है। इस बीमारी के कारण उन्हें करियर से कुछ समय का ब्रेक लेना पड़ा और गहन इलाज एवं थेरेपी से गुजरना पड़ा।

सामंथा रुथ का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में सामंथा ने अपनी फिल्म 'शुभम' को प्रोड्यूस किया है। इस समय वह राज डीके की बड़ी सीरीज 'रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें आदित्य कपूर, वामीका गब्बी और जयदीप आदि हैं।

तेलंगाना फिल्म फेस्टिवल अनन्या नागल्ला को मिले दो अवॉर्ड

हैदराबाद में तेलंगाना-नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ। इसमें तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। कई कलाकारों को अवॉर्ड भी मिले। इस लिस्ट में साउथ एक्ट्रेस अनन्या नागल्ला भी शामिल रहीं। एक्ट्रेस अनन्या नागल्ला तेलंगाना-नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, 'मैं आज तेलंगाना और असम फिल्म एसोसिएशन के प्रोग्राम के लिए यहां आई थी। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मुझे दो अवॉर्ड मिले हैं।'

आर्यन खान का लग्जरी ब्रांड इवेंट, इब्राहिम और रूमर्ड गर्लफ्रेंड पलक ने ली अलग-अलग एंट्री

आर्यन खान ने बतौर डायरेक्टर 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज बनाई। यह सीरीज काफी चर्चित रही। डायरेक्शन के अलावा वह बिजनेस में भी पहले ही हाथ आजमा चुके हैं। आर्यन का एक लग्जरी ब्रांड भी है। इस ब्रांड से जुड़ा एक इवेंट शुक्रवार रात मुंबई में हुआ। जानिए, इसमें कौन-कौन शामिल हुआ। अपने लग्जरी ब्रांड के इवेंट में आर्यन खान सबसे पहले नजर आए। पैपराजी को पोज देते हुए वह बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराए।

पलक तिवारी और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली की डेटिंग की चर्चा काफी समय हो रही है। दोनों कई इवेंट्स में पहुंचते हैं। आर्यन खान के इवेंट में भी दोनों को देखा गया लेकिन पलक और इब्राहिम ने अलग-अलग एंट्री ली। दोनों ने अलग-अलग ही पैपराजी को पोज दिए, फोटो क्लिक करवाए।

इस इवेंट में ओरी को भी देखा गया। हाल ही में इस इंफ्लुएंसर का नाम एक ड्रग्स केस में सामने आया है। पुलिस ने ओरी को समन भी भेजा था, लेकिन वह दिए गए समय पर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। एक्ट्रेस अवनीत कौर के अलावा कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को भी आर्यन खान के इवेंट में देखा गया। अवनीत का लुक काफी चर्चा में रहा।

महिलाएं जब एक दूसरे का साथ देती हैं तो जादू होता है

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'स्त्री ऊर्जा' यानी फेमिनिन एनर्जी के बारे में एक लंबी पोस्ट लिखी है। पोस्ट में उन्होंने बताया है कि असली स्त्री ऊर्जा क्या होती है। रश्मिका ने बताया है कि अगर कोई महिला अपने अंदर की आवाज से जुड़ जाती है, तो उसके अंदर कई बदलाव आते हैं।

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में रश्मिका ने लिखा 'स्त्री ऊर्जा में एक खास जादू होता है। जब आप खुद से जुड़ जाती हैं, तो आप चीजों को साफ-साफ देखने लगती हैं। लोगों को पहचान जाती हैं और स्थितियों को पहले से समझ जाती हैं। कई बार आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। आपका मन आपको सावधान करता है। हालांकि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि जिंदगी बहुत जटिल है।'

महिलाएं जब साथ देती हैं तो जादू होता है

रश्मिका ने आगे लिखा 'महिलाएं जब एक-दसरे को सहारा देती हैं और सिर्फ यह कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक अलग जादू होता है। उस कोमलता में बहुत ताकत होती है। स्त्री शक्ति कमजोर नहीं है। हां यह कोमल जरूर है लेकिन यह मजबूत है और प्यार से भरी हुई है। जब महिलाएं इस तरह की ऊर्जा के साथ एकजुट होती हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता।'

रश्मिका ने आखिर में लिखा 'मैं देख रही हूं कि आप में से बहुत सी महिलाओं में यह शक्ति है। जिन्हें अभी तक इसके बारे में समझ नहीं है वह जल्द ही इसके बारे में समझेंगी और इसे महसूस करेंगी। जल्द ही इसे पा लेंगी और मजबूर स्त्री ऊर्जा बन जाएंगी।'

'द गर्लफ्रेंड' के बारे में

हाल ही में रिलीज हुई रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' का निर्देशन राहुल रविंद्रन ने किया है। इसके लेखक भी वही हैं। फिल्म के निर्माता अल्लू अरविंद, धीरज मोगीलिनेनी और कोप्पिनीदी विद्या हैं। इसमें रश्मिका मंदाना के अलावा दीक्षित शेट्टी, अनु इमैनुएल, रोहिणी, कौशिक मेहता और राव रमेश हैं।

अमिताभ बच्चन ने मुझे लगभग मार दिया था', मनोज बाजपेयी ने सुनाया 26 साल पहले का मजेदार किस्सा

अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ एक मजेदार लेकिन डरावना वाकया शेयर किया है। उन्होंने 26 साल पहले की एक घटना को याद किया जिसमें अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक स्टंट करने के लिए मनाया। इसमें मनोज बाजपेयी की जान जा सकती थी।

अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी को ऊंचाई से जुड़ा एक स्टंट करने को कहा था। मनोज बाजपेयी ने बताया 'एक बार अमिताभ बच्चन ने मुझे लगभग जान से मार दिया था। मुझे चक्कर आता है। उस वक्त मैं एक फिल्म में काम कर रहा था। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने मुझे झरने से कूदने को कहा, जो लगभग 150-200 फीट ऊंचा था।'

अमिताभ बच्चन ने मनोज बाजपेयी को मनाया

मनोज बाजपेयी ने आगे बताया 'मैंने इतनी ऊंचाई से कूदने से मना कर दिया। मैंने कहा, मैं मर जाउंगा या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इस काम को करने के लिए मुझे कोई नहीं मना सका। इसके बाद सब लोग अमिताभ बच्चन के पास गए।' मनोज बाजपेयी ने बताया 'अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा, देखो मनोज मैं यहां हूं, हम सिर्फ 50 फीट ऊपर जाएंगे। ज्यादा ऊपर जाने से खतरा हो सकता है। उन्होंने हम पर भरोसा किया है। पीछे मत हटो'

मनोज बाजपेयी का किस्सा सुन कर सभी लोग हंस पड़े

मनोज बाजपेयी ने आगे बताया कि उन्होंने यह स्टंट करने से दोबारा मना कर दिया। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा 'सुनो अगर तुम्हें कुछ होता है तो जया बच्चन से मेरी शिकायत कर देना। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।' मनोज बाजपेयी का यह वाकया सुन कर शो में मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

21 नवंबर को रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की सीरीज

मनोज बाजपेयी की अदाकारी वाली वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' 21 नवंबर को रिलीज हुई। इसमें जयदीप अहलावत, निमरत कौर, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, दर्शन कुमार, वेदांत सिन्हा और श्रेया धनवंतरी जैसे कलाकार हैं। इस वेब सीरीज के शुरुआती दो सीजन काफी पापूलर हुए और दर्शकों ने भरपूर प्यार भी दिया। अब फिर से वही जादू दिख रहा है।

हरित कौशल विकास : आदिवासी युवाओं से जैव विविधता संरक्षण को नई दिशा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर जैव-विविधता संरक्षण को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी उद्देश्य से बोर्ड ने वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह विशेष प्रशिक्षण इसलिए तैयार किया गया है ताकि जंगलों में रहने वाले युवाओं को जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी जानकारी, व्यवहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिल सकें।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का यह प्रयास आदिवासी युवाओं को कौशल, ज्ञान और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण को भी सशक्त बना रहा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आजीविका के नए अवसर प्रदान करना, पर्यावरण मित्र करियर की ओर प्रेरित करना तथा उन्हें स्थानीय संसाधनों के संरक्षण में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण में युवाओं को राष्ट्रीय उद्यान गाइड, पर्यटक गाइड, प्राकृतिक इतिहास प्रदर्शक, वन संसाधन सहायक, पारंपरिक वन संरक्षण तकनीकों, और वन आधारित आजीविका से जुड़े विभिन्न कौशल सिखाए गए।

105 युवाओं ने प्रथम चरण में दिया गया प्रशिक्षण

इसी कड़ी में राज्य के जांजगीर, कटघोरा, कोरबा, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा आदि कई जिले से कुल 105 युवाओं ने प्रथम चरण में भाग लिया। प्रशिक्षण 10 से 30 दिनों तक चला और इसमें युवाओं को बिना किसी शुल्क के फील्ड भ्रमण, जैव विविधता पहचान, पारिस्थितिक संवेदनशीलता, वन संपदा का संरक्षण, औषधीय पौधों की पहचान और दस्तावेजीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान दिया गया।

विशेष रूप से आकांक्षी सुकमा जिले के 65 युवाओं ने जंगलों में पाए जाने वाले 153 प्रजातियों के पौधों और 47 पक्षी प्रजातियों की पहचान की। वन विभाग के विशेषज्ञों ने उन्हें हर्बेरियम बनाने, जैव-विविधता सर्वे तथा उपकरणों के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया।

इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग यह भी है कि युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करना सिखाया जा रहा है। इससे स्थानीय समुदायों में जैव-विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में ग्रामीणों की भागीदारी भी मजबूत हो रही है।

दुर्लभ पौधों और जीवों की कर पा रहे हैं पहचान

इस प्रशिक्षण का मुख्य प्रभाव यह रहा कि अब युवा अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ पौधों और जीवों की पहचान कर पा रहे हैं। कई प्रशिक्षण प्राप्त युवा ईको-गाइड, नेचर गाइड, बैचलर सर्वे टीम और ईको-टूरिज्म गतिविधियों से जुड़ कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

गांव के नौनिहालों को मिली सुरक्षित और आधुनिक शुरुआत

आंगनबाड़ी भवन निर्माण में मनरेगा ने निभाई अहम भूमिका

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आंगनबाड़ी सेवाओं का व्यापक सुदृढ़ीकरण ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में बच्चों के समग्र विकास का मजबूत आधार बन रहा है। प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा और अनुशासन की नींव रखने वाले आंगनबाड़ी केंद्र अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर नौनिहालों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।

पिछले एक दशक में महात्मा गांधी नरेगा और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले में 148 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूरा किया गया है। इस मॉडल ने हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण और शिक्षा गतिविधियों से जोड़कर उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

वनांचल क्षेत्र सोनहत में 26 और बैकुण्ठपुर क्षेत्र में 122 नए आंगनबाड़ी भवन तैयार किए गए हैं। सोनहत में 133 लाख रुपये और बैकुण्ठपुर में 9 करोड़ 9 लाख रुपये से अधिक की राशि मनरेगा से स्वीकृत की गई। नए मानक के अनुसार प्रति भवन 11.69 लाख रुपये की लागत निर्धारित है, जिसमें 8 लाख रुपये मनरेगा से उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2024 से पूर्व स्वीकृत भवनों की लागत 6.45 लाख रुपये थी, जिसमें 5 लाख रुपये मनरेगा से प्रदान किए जाते थे।

विभागीय मांग के आधार पर जनपद पंचायतों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है। प्रत्येक भवन का निर्माण ग्राम पंचायतों की देखरेख में गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कराया जाता है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने हाल ही में सोनहत के लिए 2 नए आंगनबाड़ी भवन और बैकुण्ठपुर के लिए 23 नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी है। सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

कोरिया जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों का यह सुदृढ़ विस्तार बाल विकास के क्षेत्र में एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो ग्रामीण नौनिहालों को बेहतर भविष्य की मजबूत नींव प्रदान कर रहा है।

कृषि विभाग के समन्वित प्रयासों से किसानों के समृद्धि के द्वार खुले

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महासमुंद जिले में कृषि विकास को गतिशील एवं लाभकारी बनाने के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। आधुनिक सिंचाई तकनीकों के विस्तार से लेकर किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं तक, जिले ने लक्ष्य प्राप्ति में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सफल क्रियान्वयन ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के साथ जल संरक्षण, फसल उत्पादकता वृद्धि और किसानों की आर्थिक उन्नति की दिशा में विशेष योगदान दिया है।

महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। निर्धारित 151 हेक्टेयर सिंचाई लक्ष्य के विरुद्ध 84

कृषकों के खेतों में 149.66 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था स्थापित की गई। लक्ष्य के लगभग पूर्ण होने से किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का महत्वाकांक्षी लाभ मिला है। वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विभाग ने कुल 264 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली विस्तार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 235 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई तथा 29 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई स्थापित की जाएगी। इस योजना से जल संरक्षण, फसलों की उत्पादकता वृद्धि और कृषि लागत में कमी की दिशा में प्रगति होगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिले में 1,26,234 किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है और पात्र किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत जिले में 25.25 करोड़ रूपए की राशि किसानों को उनके खाते में प्राप्त हुई है। जिले में 1,39,063 किसानों का लैंड सीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार 1,37,835 किसानों की आधार सीडिंग तथा 1,40,733 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।

सूरजपुर में मीठा शक्ति आहार एवं पौष्टिक दलिया निर्माण संयंत्र शुरू

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया लोकार्पण, मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में महिलाओं आजीविका का नया अवसर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के मामले में एक और उपलब्धि छत्तीसगढ़ ने आज दर्ज की है। सूरजपुर जिले में एक नए पूरक पोषण आहार निर्माण संयंत्र की शुरूआत हुई है। यह सयंत्र सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के दर्रीपारा में आकांक्षा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित होगा। इस संयंत्र का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया और महिला समूहों से जुड़ी सदस्य महिलाओं को इस के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।

सूरजपुर जिले के दर्रीपारा में शुरू हुए इस पूरक पोषण आहार निर्माण संयंत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य में पूरक पोषण निर्माण में महिला स्व-सहायता समूहों की सहभागिता की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा मोदी जी के गारंटी को पूरा करने के लिए पूरक पोषण आहार निर्माण की सर्वप्रथम जवाबदारी महिला समूहों को रायगढ़ जिले में सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की मौजूदगी 17 अगस्त 2025 को कोतरलिया में सर्वप्रथम पूरक पोषण आहार निर्माण संयंत्र का शुभारंभ हुआ था। इसके पश्चात बस्तर और दंतेवाड़ा में पूरक पोषण आहार निर्माण संयंत्र के संचालन की जिम्मेदारी महिला समूहों को सौंप दी गई है। सूरजपुर के दर्रीपारा में शुरू हुआ यह चौथा पूरक पोषण आहार है।

इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सूरजपुर के दर्रीपारा में शुरू हुए इस आधुनिक संयंत्र से मीठा शक्ति आहार एवं नमकीन पौष्टिक दलिया का उत्पादन होगा, जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पोषक पूरक आहार उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी की कुपोषण मुक्त भारत की प्रतिबद्धता और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पोषण युक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि दर्रीपारा में शुरू हुए इस संयंत्र के माध्यम से भैयाथान परियोजना के अंतर्गत आने वाले 366 आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से मीठा शक्ति आहार एवं पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होगा, आपूर्ति व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी।

मंत्री राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिला समूहों के विस्तार, प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाओं के लिए हरसंभव सहयोग देगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह, जनपद उपाध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष सुनील साहू, एसडीएम चांदनी कंवर, तहसीलदार शिवनारायण राठिया, जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पूरक पोषण आहार उत्पादन का दायित्व पुनः महिला स्व सहायता समूहों को सौंपे जाने के लिए प्रथम चरण में राज्य के 6 जिले चयनित किए गए हैं, जिसमें रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार, बस्तर, दंतेवाड़ा और सूरजपुर शामिल हैं। 4 जिलों में पूरक पोषण आहार संयंत्र का शुभारंभ हो चुका है। जल्द ही बलौदाबाजार और कोरबा में भी पूरक पोषण आहार निर्माण संयंत्र शुरू होगा। इससे महिला समूहों के लिए नए रोजगार और आजीविका अर्जन का नया अवसर मिलेगा।

खरीफ उपार्जन शुरू होते ही धमतरी में लौटी रौनक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेशभर की तरह धमतरी जिले में भी खरीफ उपार्जन वर्ष 2025-26 की शुरुआत 15 नवंबर से सुचारू रूप से हो चुकी है। खरीदी केंद्रों में जहाँ किसानों के चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता दिखाई दे रही है, वहीं गांवों में श्रमिक परिवारों के बीच भी खुशी का माहौल है।

धान खरीदी से जुड़े कार्यों ने ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार एवं अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ा दिए हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था में नई जान आई है। संबलपुर गांव के खरीदी केंद्र में काम कर रहीं ईश्वरी यादव और विद्या मरकाम जैसी महिलाएँ इस बदलाव का सशक्त उदाहरण हैं।

धान के कट्टों की सिलाई और भराई में व्यस्त ये महिलाएँ बताती हैं कि खरीफ सीजन उनके लिए उम्मीद और आत्मनिर्भरता का समय बन गया है। गांव की 5-6 महिलाएँ मिलकर प्रतिदिन 400 से 500 कट्टे तैयार करती हैं, जिससे प्रत्येक महिला को सीजन के दौरान लगभग 20 से 22 हजार रुपये की आय हो जाती है। यह राशि उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहारा साबित होती है। इन महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें मजदूरी के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब धान खरीदी केंद्रों में मिल रहा स्थानीय कार्य उन्हें सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। भुगतान समय पर होता है और कार्य के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

धान खरीदी प्रक्रिया किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ हमालों, परिवहनकर्ताओं, तौलदारों, डेटा-एंट्री ऑपरेटरों और सहायक कर्मचारियों के लिए भी व्यापक रोजगार सृजित करती है। सुगम व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया ने इस सीजन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बना दिया है। सरकार द्वारा समय पर समर्थन मूल्य भुगतान, सुरक्षित भंडारण व्यवस्था और खरीदी केंद्रों में बेहतर प्रबंधन ने ग्रामीण जनता के भरोसे को और मजबूत किया है।

भरतपुर में नई ग्रामीण बस सेवा शुरू

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा से ग्रामीणों में खुशी की लहर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जनहितकारी सोच एवं मंशानुरूप परिवहन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक में ग्रामीण बस सेवा के तहत नई बसों का शुभारंभ किया गया।

उल्लेखनीय है कि परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर, सुगम और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगातार साकार हो रहा है। उनकी प्राथमिकता हमेशा से अंतिम व्यक्ति तक शासकीय सुविधाएं पहुँचाना रही है। ग्रामीण बस सेवा इसी संकल्प का प्रभावी उदाहरण है, जिसने गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में नई ऊर्जा प्रदान की है।

नई बस सेवा शुरू होने से भरतपुर एवं आसपास के गांवों के विद्यार्थियों, महिलाओं, मजदूरों तथा आम लोगों को अब नियमित और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सकेगी। अब विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज पहुँचने में आसानी होगी, महिलाएं बिना परेशानी अस्पताल, बाज़ार और आवश्यक कामों के लिए अपने गंतव्य तक सुगमता से यात्रा कर सकेंगी, वहीं मजदूर वर्ग को रोजगार स्थलों तक पहुंचने में समय और सुविधा दोनों मिलेंगी।

इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में बसों को हरी झंडी दिखाकर उनके निर्धारित मार्गों पर रवाना किया गया। बसों के प्रस्थान के साथ ही ग्रामीणों में उत्साह और प्रसन्नता का माहौल रहा। लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सेवा उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करती है।

ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल: यह बस सेवा केवल परिवहन व्यवस्था का विस्तार नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव और शहर के बीच संपर्क बढ़ेगा तथा विकास की गति और तेज होगी। मुख्यमंत्री साय की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक टीम के समन्वित प्रयासों का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्र अब सुविधाओं और विकास के नए मानक स्थापित कर रहे हैं।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष माया प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष हीरालाल मौर्य, जनपद सदस्य सुखलाल मरावी, नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल पटेल, उपाध्यक्ष निलेश मिश्रा, जनपद सीईओ, परिवहन अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से जनता हो रही लाभान्वित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। योजना का मुख्य लक्ष्य शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में नगर पालिका परिषद महासमुंद के विभिन्न वार्डों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री अशोक सलामे की देखरेख में शिविरों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट मैनेजर धर्मेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि महासमुंद जिले के शहरी क्षेत्रों में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से अब तक लगभग पौने दो लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इनमें से 50 हजार से अधिक नागरिकों के मुफ्त लैब टेस्ट कराए गए हैं तथा डेढ़ लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। शिविरों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन की टीम द्वारा मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श और जांच की सुविधा दी जाती है।

योजना के अंतर्गत 170 प्रकार की आवश्यक दवाइयां तथा 41 प्रकार की लैब जांच पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही नगर के सफाई मित्रों के लिए भी प्रति माह नियमित स्वास्थ्य जांच की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे उनके स्वास्थ्य संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा दल शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर नागरिकों को उनके घर के पास ही उच्चतम स्वास्थ्य परामर्श, जांच और दवाइयों की सुविधा प्रदान कर रहा है।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरल उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

पति ने पत्नी को डंडे से पीटकर कर दी हत्या, बच्चों के सामने किया मर्डर

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक युवक ने डंडे से पीट-पीटक कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने पत्नी को बच्चों के सामने ही मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बस्तर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, ग्राम करमरी भाटागुड़ा का निवासी रेंगा बघेल (37) बेरोजगार था। वो यहां-वहां घूमते रहता था। जबकि उसकी पत्नी पूर्णिमा (29) मजदूरी करती थी। खुद घर चलाती थी। वहीं एक दिन पहले दोनों के बीच रात में खाना खाने को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि युवक ने अपनी पत्नी की पिटाई करनी शुरू कर दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्चे और अन्य परिजन भी अपने कमरे से बाहर निकले। उनके सामने ही युवक ने अपनी पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। बीच-बचाव से पहले ही पत्नी की मौत हो गई थी। पड़ोसियों ने भी आवाज सुनी थी। जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचे। पुलिस को वारदात की जानकारी दी गई। जिसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ लिया है।

ऑपरेशन सुरक्षा : दुर्ग जिले में हादसों में आई कमी, सड़क सुरक्षा सुधार का मिल रहा फायदा

दुर्ग पुलिस ने जारी किए आंकड़े, चालानी कार्रवाई हुई दो गुनी

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा उपायों का प्रभावी असर देखने को मिल रहा है। साल 2024 की तुलना में दुर्ग जिले में न सिर्फ हादसों में कमी दर्ज किया गया है बल्कि ब्लैक व ग्रे स्पॉट में मृत्यू के आंकड़े भी घटे है। दुर्ग पुलिस की सख्त कार्रवाइयों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पिछले साल की तुलना में काफी बढ़े हैं। यह इसलिए है क्योंकि यातायात पुलिस पूरी तल्लीनता के साथ जांच कार्रवाई में लगी हुई है।

दुर्ग एसएसपी द्वारा साल 2024 और साल 2025 में हुए हादसों व इनसे हुए नुकसान का एक तूलनात्मक आंकडा जारी किया है। इन आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जिले में पुलिस व यातायात विभाग की सतर्कता से सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक कमी दर्ज की गई है। ऑपरेशन सुरक्षा के तहत दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इंजीनियरिंग तथा एन्फोर्समेंट आधारित दोहरी रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। विभागीय विश्लेषण में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं में कमी तभी संभव है जब सड़क संरचना में सुधार और प्रवर्तन दोनों समानांतर रूप से कार्य करें। इसी आधार पर यातायात पुलिस द्वारा नगर निगम, पीडब्लूडी,एनएचएआई तथा बीएसपी प्रबंधन को विभिन्न अवसंरचनात्मक सुधारों हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं।

चालानी कार्यवाही

- माह अप्रैल से नवम्बर 2024 तक 22188 प्रकरण में कुल 8 लाख 13 हजार 1900 रुपए
- माह अप्रैल से 14 नवम्बर 2025 के बीच 49853 प्रकरणों में 15 लाख 75 हजार 9000 रुपए

अभियान के कारण सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में गिरावट

इंजीनियरिंग सुधारों के प्रस्ताव, प्रवर्तन में वृद्धि और ऑपरेशन सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे निरंतर अभियान ने वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में स्पष्ट गिरावट दर्ज कराई है। यह समन्वित प्रयास जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंजीनियरिंग आधारित प्रमुख सुधार प्रस्ताव

- पुलगांव चौक एवं नेहरू नगर चौक पर लेफ्ट-फ्री मूवमेंट की व्यवस्था।
- असमान/क्षतिग्रस्त सड़क को समतल कर सुगम मार्ग उपलब्ध कराना।
- रेल चौक सेक्टर-6 स्थित रोटरी के आकार को कम करने का प्रस्ताव,।
- सिरसा गेट चौक पर हाई-मास्ट लाइट स्थापित करना।
- पुलगांव नाला ओवरब्रिज क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- पुलगांव से पोटिया चौक व अन्य संवेदनशील मार्गों पर स्ट्रीट लाइटिंग को दुरुस्त करना।
- बोगदा पुलिया-स्मृति नगर रोड एवं स्मृति नगर,नेहरू नगर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव।
- नेहरू नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने चारों दिशाओं में रंबल स्ट्रिप लगाने की अनुशंसा।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी

- एन्फोर्समेंट के तहत साल 2024 में 32,997 कार्रवाई और साल 2025 में अब तक 65,525 कार्रवाई
- इंटरसेप्टर आधारित साल 2024 2635 प्रकरण और साल 2025 6639 प्रकरण
- दुर्घटनाओं में कमी जनवरी-अक्टूबर के बीच साल 2024 में 746 और 2025 में 664, घायल 2024 में 653 और 2025 में 584, मृत्यु 2024 में 213 और 2025 में 190
- ब्लैक/ग्रे स्पॉट पर मृत्यु में भारी कमी : 2024 जनवरी से अक्टूबर के बीच 45 मृत्यु और साल 2025 जनवरी से अक्टूबर के बीच 4 मृत्यु

फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट गिरफ्तार, जशपुर में डर दिखाकर 30 ग्राम पंचायत सचिवों से मांगी थी रकम

श्रीकंचनपथ न्यूज

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सूचना के अधिकार का भय दिखाकर जिले के 30 ग्राम पंचायत सचिवों से रुपए मांगे। इस मामले में ग्राम पंचायत सचिवों की रिपोर्ट पर जबरन वसुली के लिए बीएनएस की धारा 308(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र का है।

दरअसल इस मामले में 19 नवंबर को ग्राम पंचायत कस्तूरा जामपानी की सचिव देवकी यादव ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जनपद पंचायत दुलदुला के माध्यम से उसे सूचना के अधिकार की धारा (6)(3) के तहत तरुण भारद्वाज का आवेदन मिला। जिसमें कि तरुण भारद्वाज के द्वारा 1 फरवरी 2020 से 21 अगस्त 25 तक 15 वें वित्त में किए गए समस्त कार्य के संबंध में इंजीनियर द्वारा जारी समस्त दस्तावेज, प्रतिवेदन जांच रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन, कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, ग्राम सभा का प्रस्ताव, रजिस्टर व बिल वाउचर इत्यादि की सत्यापित प्रति मांगी गई थी।

उक्त जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत नहीं दी जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में आवेदक तरुण भारद्वाज को सूचित किया गया था। तरुण भारद्वाज ने प्रथम अपील जनपद पंचायत दुलदुला में किया गया था, जिसकी सुनवाई 19 नवंबर 2025 को होनी थी। देवकी यादव ने बताया कि 18 नवंबर 2025 को प्रार्थिया के पास एक अंजान नंबर से फोन आया। कॉलर ने अपना नाम तरुण भारद्वाज बताया और बोला कि क्या आप लोग जानकारी देना चाहते हैं?, या कुछ और व्यवस्था करना चाहते हैं। व्यवस्था के संबंध में पूछने पर तरुण भारद्वाज ने कहा कि पंचायत सचिवों से 3000-3000 देने के लिए बोलो, नहीं तो वह सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाल कर सभी पंचायत सचिवों को बर्खास्त करवा देगा। इस बातचीत को देवकी यादव ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।

19 नवंबर 25 को तरुण भारद्वाज अपने सूचना के अधिकार के तहत दिए गए आवेदन की प्रथम अपील की सुनवाई हेतु, कार्यालय जनपद पंचायत दुलदुला में आया हुआ था, सभी पंचायत सचिव भी वहीं उपस्थित थे। इस दौरान भी तरुण भारद्वाज फिर से सचिवों को बर्खास्त कराने व जेल भेज देने तथा राज्य सूचना आयोग में शिकायत करने की धमकी देकर कुल 90,000 रुपए की मांग की। दो सचिवों ने भय से फोन पे के माध्यम से उसके अकाउंट में 500-500 रु. डाल भी दिए थे।

एफआईआर के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 308(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। पूछताछ पर आरोपी तरुण भारद्वाज के द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वह ग्राम अण्डा जिला शक्ति का निवासी है, उसे कहीं से जानकारी मिली थी, बहुत सारी जानकारी निकालने पर, संबंधितों को ब्लैकमेल कर, बहुत सारे रुपए कमाए जा सकते हैं, इसी लिए वह पंचायत सचिवों से रुपए ऐंठने हेतु प्लान बनाया और सूचना के अधिकार के तहत लंबी चौड़ी जानकारी की मांगी।

भिलाई गोलीकांड : हत्या का बदला लेने के लिए रची गई थी साजिश, झारखंड से दो शूटर गिरफ्तार

मामले में अब तक 09 आरोपी पकड़े गए, बाइक-पिस्टल व कारतूस बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए गोली कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में झारखंड से दो शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ ही शूटर के पास से पिस्टल व कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

दरअसल 14 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे घासीदास नगर जामुल में संतोषी नगर कैंप-2 निवासी विकास प्रजापति पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया गया था। इस मामले में शिकायत पर थाना जामुल में धारा 109 (1) बीएनएस कायम कर किया गया। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता करण साव सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आरोपी करण साव ने विकास प्रजापति की हत्या के लिए झारखंड से भाड़े के शुटर बुलवाए थे। फायरिंग के बाद वे फरार हो गए।

जामुल पुलिस ने झारखंड के झींग नगर एवं जगन्नाथपुर (रांची) के आरोपी राजेश निवासी झींगनगर हटिया, थाना बिहार सरिफ तथा बबलू उर्फ बडका जगन्नापुर, न्यू कॉलोनी रांची झारखंड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजेश आरोपी करण साव का ममेरा भाई है जो रेलवे व अन्य प्रतियोगी परीक्षा देने भिलाई आता जाता था। करण साव ने अपने चचेरे भाई शिवम की हत्या का बदला लेने के लिए राजेश की मदद लिया, राजेश साव ने बबलू उर्फ बडका व अन्य दो को हत्या करने का जिम्मा दिया। करण साव ने आरोपियों को पिस्टल, गोलियों की व्यवस्था करने के लिए 55 हजार रुपए उपलब्ध कराया था। 14 नवंबर को गोली कांड के बाद आरोपियों ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल व गोलियां करण साव को लाकर दिया और फायरिंग करने की जानकारी दी। इसके करण साव द्वारा उपलब्ध करायी गयी हीरो पैशन बाईक सीजी 07 ए.पी. 1013 में रायपुर की ओर भाग गए ।

बाईक भिलाई 03 बाजार के किनारे खडी कर आटो से रायपुर बस स्टैंड चले गए थे। आरोपियों की निशानदेही पर करण साव से घटना में प्रयुक्त पिस्टल तथा कारतूस(7.65) एवं आरोपी बबलू से कारतूस तथा बाईक हीरो पैशन जब्त किया गया है। शुक्रवार को आरोपी राजेश 29 वर्ष निवासी झींगनगर हटिया, थाना बिहार सरिफ तथा बबलू उर्फ बडका 27 वर्ष जगन्नापुर, न्यू कॉलोनी रांची झारखंड को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया गया है अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

32 युवकों से 33.50 लाख की ठगी: रेलवे माल गोदाम में नौकरी का दिया झांसा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रेलवे माल गोदाम में स्थायी नौकरी का झांसा देकर 33.50 लाख रुपए ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब वेदांता नगर में रहने वाली रीति देशलहरा ने 18 नवंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि नवरात्रि पर्व 2022 के दौरान उनका पुराना परिचित बिशेश्वर मारकंडे उनके घर आया था। बिशेश्वर ने रीति देशलहरा के पति को बताया कि वह रसमड़ा रेलवे माल गोदाम में लीडर है। वहां स्थायी नौकरी दिलवा सकता है। उसने दावा किया कि वह तीन महीनों के भीतर नियुक्ति करा देगा। इसके लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख 50 हजार रुपए देने होंगे। उसके झांसे में आकर कुल 32 युवकों से पैसे जुटाए।

24 दिसंबर 2022 से 24 अप्रैल 2023 के बीच आरोपी कई बार रीति देशलहरा के घर उमरपोटी पहुंचे। उन्होंने युवाओं को नौकरी का आश्वासन दिया और अलग-अलग किस्तों में उनसे रुपए वसूले। हालांकि, महीनों बीत जाने के बाद भी न तो नौकरी मिली और न ही पैसे लौटाए गए। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि बिशेश्वर पहले माल गोदाम में हमाली का काम करता था। इसी दौरान उसकी पहचान हेमंत साहू से हुई, जो खुद को रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन का सचिव बताता था। प्रमोद मारकंडे भी इस ठगी के गिरोह का हिस्सा था।

एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि हेमंत साहू बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच देता था। बिशेश्वर उम्मीदवार लाता था और रकम हेमंत को सौंप दी जाती थी। रेल माल गोदाम में पदस्थ कर्मचारी होना दिखाकर इन्हें जुगाड़ करने का भरोसा दिलाया गया था। युवकों ने जब बार-बार नौकरी की स्थिति पूछी तो आरोपियों ने बहाने बनाकर उन्हें गुमराह किया। शिकायतकर्ता से भी कई महीनों तक पैसे लौटाने से इनकार किया गया। ठगे गए पैसों का इस्तेमाल आरोपियों ने गाड़ियां खरीदने, घर बनाने और निजी खर्चों में करना स्वीकार किया।

दो महीने में जब्त 200 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर

रायगढ़। पुलिस विभाग ने शुक्रवार को पिछले दो महीने में जब्त किए गए 200 मॉडिफाइड साइलेंसर नष्ट किए। यातायात थाना के पीछे मॉडिफाइड साइलेंसर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर उन बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई थी, जिन्होंने मानक साइलेंसर हटाकर तेज और कर्कश ध्वनि वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए थे। नियम उल्लंघन करने वालों से समन शुल्क वसूलते हुए उनके वाहनों में मानक साइलेंसर लगवाए गए।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 13.11.2025

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)
(प्रथम आमंत्रण)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदायें प्रपत्र "अ" में प्रतिशत दर पर दिनांक 03.12.2025 तक आमंत्रित की जाती हैः-

निविदा आमंत्रण सू.क./ सि.क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
277/179921	बेमेतरा संभाग के अंतर्गत विभिन्ना मार्गो में रोड मार्किग एवं सूचना पलक का कार्य	40.00
278/179922	लोक निर्माण विभाग, अनुविभाग क्रं. 01 बालोद के अंतर्गत जिला बालोद के विद्यमान सड़को के रोड़ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुधार एवं सुरक्षा उपाय कार्य	168.63
279/179924	खैरागढ संभाग के अंतर्गत विद्यमान सड़को के रोड़ सेफ्टी सड़क सुधार एवं सुरक्षा उपाय कार्य	161.41
280/179925	जिला राजनांदगांव के शहरी क्षेत्र में रोड़ सेफ्टी के अंतर्गत स्पीड ब्रेकर साईन बोड़ एवं अन्य बोर्ड फर्नीचर कार्य	20.00
281/179926	उपसंभाग क्रं. 01 राजनांदगांव के अंतर्गत राज्य मार्ग पर जंक्शन सुधार का कार्य एवं आई.आर.सी. के प्रावधानुसार कैश बैरियर लगाने का कार्य	130.62
283/179927	जिला कबीरधाम के अंतर्गत राज्य मार्ग पर जंक्शन संधार का कार्य एवं आई.आर.सी. के प्रावधानुसार कैश बेयर का कार्य	43.95

टीप

1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागीय वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाऊनलोड की जा सकती है ।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायें ।

जी-252604935/8

अधीक्षण अभियंता
लोकनिर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल, दुर्ग
दूरभाष- 0788-2210876

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/चार/रा.वि/2025/2401315 — भिलाई, दिनांक 21/11/2025

-:: फ्री-होल्ड हेतु दावा आपत्ति सूचना ::-

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के आदेश कमांक एफ-8-5/2022/18 के सम संख्यक आदेश दिनांक 06.07.2022 द्वारा नगरीय निकायों के स्वयं के आधिपत्य/स्वामित्व के लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय/व्यवसायिक (भवनों /फ्लैट्स/भू-खण्डों/परिसर/दुकानों) को संबंधित नगरीय निकायो राजस्व विभाग से विधिवत भू-स्वामित्व प्राप्त होने पर फ्री-होल्ड के रूप में संपरिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

फ्री होल्ड के रूप में सपरिवर्तन के लिये निम्नांकित भूखण्ड धारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर फ्री-होल्ड के रूप संपरिवर्तन किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध मे किसी प्रकर की कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

क.	पट्टाधारी का नाम पिता/पति का नाम	योजना का नाम	ब्लाक क. /भूखण्ड क.	आकार
1	श्री राधेलाल देवांगन आ0 स्व0 श्री ढेलउ राम देवांगन	कृष्णा नगर आ.यो. भिलाई	-	805 व0फु0
2	श्री गौरेश पटेल आ0 श्री नरहरी भाई पटेल	नंदनी रोड शास्त्री मार्केट व्यवसायिक व्यवस्थापनप	शाप नं. 19	378.148 व0फु0
3	श्रीमती पुर्णिमा सेठ पति धनुज सेठ, श्रीमती पुष्पा सेठ पति स्व0 एस0एस0 सेठ, श्री पंकज सेठ, अनुज सेठ, गौरव सेठ तीनों के आ0 स्व0 एस.एस. सेठ	नंदनी रोड सी ग्रुप व्यवसायिक व्यवस्थापन भिलाई	52	240 व0फु0
4	श्री शिवनाथ सिंह आ0 नथुनी सिंह	सुपेला मार्केट	38/11	198 व0फु0
5	श्रीमती पुष्पा सेठ पति स्व0 एस0एस0 सेठ	नंदनी रोड सी ग्रुप व्यवसायिक व्यवस्थापन भिलाई	भूखण्ड क. 41	240 व0फु0
6	श्रीमती अरुंधती ओझा पति श्री दिलीप कुमार ओझा	जवाहर नगर हुडको भवन एल.आई.जी. 2ए	25/10	40.5 व0मी0

राजस्व अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक, बोले-

प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का पहुंचे लाभ

जनकल्याणकारी योजनाओं का तेज और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की व्यापक और विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिशा समिति की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन्हीं बैठकों के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक 6 माह में दिशा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि 26 विभागों के अंतर्गत कुल 81 योजनाएँ संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे जिले स्तर पर आयोजित प्रत्येक तिमाही दिशा समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बैठक की नियमितता, बेहतर समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति विकास कार्यों की दिशा तय करने वाली प्रमुख संस्था है।

मुख्यमंत्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित पीएम जनमन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्थिति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए और किसी भी पात्र किसान को लाभ से वंचित न रखा जाए। उन्होंने इस दौरान वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रारम्भ हुई डेयरी समग्र विकास योजना की समीक्षा के दौरान धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के साथ-साथ पारंपरिक रूप से दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को भी योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि योजना को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत, तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर दिया।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जारी आयुष्मान कार्ड एवं वय वंदन कार्ड की संख्या पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने नियद नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने और हितग्राहियों की सुविधा के लिए राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं पोषण योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मध्याह्न भोजन की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ प्रदेश के विकास का आधार हैं। उन्होंने 'न्योता भोज' पहल की निरंतरता की जानकारी ली और जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री ने टेलिकॉम सेक्टर में भारत नेट परियोजना की प्रगति धीमी होने पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने फाइबर नेटवर्क का कार्य शीघ्र पूर्ण करने और बस्तर एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी भी ली गई। बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित विभागों के भारसाधक सचिव एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के विकास में जुड़ा नया आयाम

युवाओं ने पाया अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग का अवसर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के विकास में नया आयाम जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा अब दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक में अपनी जगह बना रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्रांति के साथ छत्तीसगढ़ देश के उच्च-प्रौद्योगिकी मानचित्र पर उभर रहा है। पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा राज्य में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और केंद्र सरकार की अग्रणी तकनीकी नीतियों का परिणाम है।

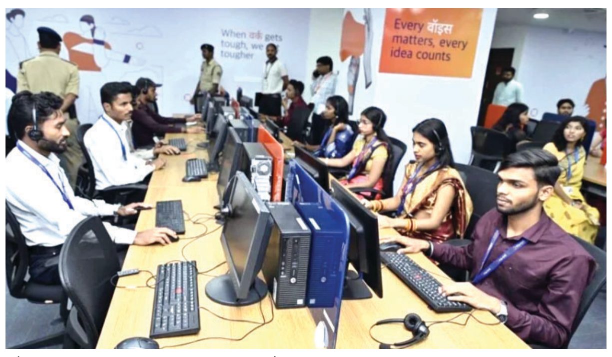

पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी है, छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। डेढ़ लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स का उत्पादन करेगा, जो टेलीकॉम, 6G/7G, लैपटॉप, पावर-इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उभरती तकनीकों में उपयोग होंगे। इस प्लांट से छत्तीसगढ़ के अनेक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ने छत्तीसगढ़ के चयनित युवाओं की पहली सूची जारी की है, जिनमें अधिकांश छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग और कॉमर्स ग्रेजुएट्स शामिल हैं। चयनित युवाओं में में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से कुल 12 युवा शामिल हैं। इनमें दुर्ग से आभार मेहूंकर (B.Tech–EEE), भिलाई से अभिषेक काशी (B.Tech– E&T), बालोद से नवीन कुमार देवांगन (B.Tech–ME), रायपुर से कुणाल यादव (BE– Mechanical), बस्तर से तुषार देवांगन (B.Tech –E&T), रायपुर से अपूर्व देवांगन (B.Tech –E&T), भिलाई की धारा सरपे (B.Tech –EEE), रायपुर के अरिन सोनी (B.Tech –E&T), रायगढ़ की तरू यादव (B.Tech –E&T), भिलाई के तुषार कुमार ठाकुर (BE– Mechanical), रायपुर के भूपेंद्र यादव (B.Com) तथा बालोद के अबिश सी. थॉमस (M.Com) को प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के लिए चयनित किया गया है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि चयनित युवाओं को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं के एयर ट्रैवल, आवास, भोजन सहित सभी खर्च कंपनी वहन करेगी। इसके बाद चयनित युवाओं को एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस स्थित पॉलीमैटेक के वैश्विक प्लांट्स में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सभी चयनित उम्मीदवार फ्रेश इंजीनियर्स हैं। मार्च 2026 तक चयनित युवाओं की संख्या बढ़कर 200 से 250 तक हो जाएगी।

प्रदेश के विकास में एक नया तकनीकी अध्याय जुड़ रहा

सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के विकास में एक नया तकनीकी अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप छत्तीसगढ़ अब उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेज़ी से उभर रहा है। पॉलीमैटेक द्वारा राज्य के युवाओं को चयनित कर उन्हें चेन्नई सहित एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस के वैश्विक प्लांट्स में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे युवाओं की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह अवसर न केवल रोजगार का माध्यम बनेगा, बल्कि युवाओं को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक की गहन समझ देकर उन्हें भविष्य का तकनीकी नेतृत्व प्रदान करेगा। हमारी सरकार हर निवेशक को पूर्ण सहयोग और हर युवा को विश्वस्तरीय कौशल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है कार्यः मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ 25 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की 25 वर्ष की स्वर्णिम विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बस्तर सहित पूरे प्रदेश में विकास में बाधक नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में किए जा रहे प्रयासों से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और बस्तर अपने मूल स्वरूप में भयमुक्त होकर प्रदेश के विकास में बेहतर भागीदारी देगा।

श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के माध्यम से बस्तर की संस्कृति और प्रतिभा को दुनिया ने देखा है। बस्तर में शांति, समृद्धि और खुशहाली के नए युग का आरंभ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी दृढ़ता से लागू है। पूर्व में जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुए, उस पर कड़ा प्रहार किया गया है, जिसका परिणाम भी सभी देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने भूखमरी जैसे अभिशाप को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए थे, जिसके तहत गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया गया। साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को आज आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लगभग सभी गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण 'चरण पादुका योजना' को भी पुनः प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नई उद्योग नीति के आकर्षक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। अब तक राज्य सरकार को पौने आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे आने वाले वर्षों में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

प्रख्यात साहित्यकार विनोद शुक्ल को 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य जगत के प्रतिष्ठित 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य की उस विराट परंपरा के प्रतिनिधि हैं, जिसने अपनी सादगी, संवेदना और अद्भुत लेखन-शक्ति से साहित्य की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उनकी लेखनी ने न केवल हिंदी भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि पाठकों की अनेक पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि विनोद कुमार शुक्ल को यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान साहित्य जगत में उनके अद्वितीय योगदान को प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री साय ने विनोद कुमार शुक्ल के सुदीर्घ, स्वस्थ और सक्रिय जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका रचनात्मक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।

सुव्यवस्थित और डिजिटल व्यवस्था से बढ़ा किसानों का भरोसा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बेमेतरा के ग्राम करेसरा के किसान भगवानी राम ने इस साल समर्थन मूल्य पर 80 क्विंटल धान बेचा है। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी के लिए की गई सुचारू, पारदर्शी और किसान हितैषी व्यवस्था से उन्हें अपना धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। धान उपार्जन केंद्र में पहुंचने पर तौल से लेकर भुगतान तक हर चरण में सुगम व्यवस्था के कारण भगवानी राम जैसे किसानों का व्यवस्था पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है। डिजिटल टोकन, सुव्यवस्थित तौलाई, पारदर्शी गुणवत्ता परीक्षण तथा समय पर भुगतान की गारंटी किसानों की मेहनत को सही मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भगवानी राम बताते हैं कि इस बार खरीदी केंद्र की व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुव्यवस्थित थी। लंबी लाइनों से मुक्ति, तौलाई में पारदर्शिता, समय पर टोकन, शेड, पीने का पानी और आराम जैसी सुविधाओं ने किसानों के लिए धान बेचने की प्रक्रिया को आसान और तनावमुक्त बना दिया है।

आर्थिक उन्नति की ओर कदमः 80 क्विंटल धान बेचने से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भगवानी राम अपने परिवार और कृषि के विकास के लिए करना चाहते हैं। वे इस कमाई को खेती के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने, अगली फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज व उर्वरकों की व्यवस्था करने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार तथा घर की जरूरतों व बच्चों की शिक्षा में निवेश जैसे कार्यों में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।

वे कहते हैं कि फसल से हुई आय ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि भविष्य की खेती के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। शासन की किसान हितैषी नीतियों और प्रशासन की सक्रियता से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भगवानी राम की कहानी अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत है कि अनुशासित मेहनत, वैज्ञानिक विधियों और सरकारी समर्थन से खेती में आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवानी राम की कहानी बताती है कि जब व्यवस्था पारदर्शी हो और किसानों को उनका हक समय पर मिले, तो मेहनत समृद्धि में बदल जाती है।

प्रकृति, वन्यजीवन और कला का अद्भुत संगम है अचानकमार टाइगर रिजर्वः मंत्री कश्यप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर जिले में स्थित देश के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र अचानकमार टाइगर रिज़र्व का भ्रमण किया। यह क्षेत्र अपनी घनी हरियाली, स्वच्छ जलधाराओं और समृद्ध वन्यजीवन के कारण प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव प्रदान करता है। वन मंत्री कश्यप ने जंगल के भीतर विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया और वहाँ की जैव-विविधता, वन संरक्षण कार्यों तथा वन्यजीव सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।

भ्रमण के दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि अचानकमार टाइगर रिज़र्व छत्तीसगढ़ की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है, जहाँ वन विभाग द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन कार्य लगातार प्रभावी रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय

समुदायों को भी जागरूक किया जाए, ताकि वन क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूत हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित गोंड चित्रकला कलाकार सुश्री रागिनी ध्रुव ने वन मंत्री से सौहार्दपूर्ण भेंट की। उन्होंने अपनी विशिष्ट गोंड कला शैली में बनाई गई एक सुंदर पेंटिंग मंत्री श्री कश्यप को समर्पित की। वन मंत्री ने इस सम्मान के लिए कलाकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला हमारी सांस्कृतिक पहचान है और इसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्थान प्राप्त है। मंत्री श्री कश्यप ने आगे कहा कि प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत दोनों ही राज्य की ताकत हैं। इनका संरक्षण और प्रोत्साहन शासन की प्राथमिकता है। अचानकमार टाइगर रिज़र्व के अधिकारियों ने मंत्री को वन क्षेत्र में की जा रही योजनाओं, वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था, ईको-टूरिज्म गतिविधियों और समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। भ्रमण के दौरान का पूरा कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और प्रेरणादायक रहा, जिसमें प्रकृति की सुंदरता, वन संरक्षण और जनजातीय कला तीनों का मनमोहक संगम देखने को मिला।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950